अवध की आवाज

www.avadhkaawaz.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित

वर्ष–11 अंक – 193 | R.N.I.- UPHIN/2012/45127 | लखनऊ शनिवार 12 नवम्बर 2022 | पृष्ठ – 4 | मूल्य–3 रूपया

संक्षिप्त समाचार

अवध की आवाज ब्यूरो

उन्नाव। उन्नाव में पुलिस अधीक्षक उन्नाव दिनेश त्रिपाठी द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आमजन की समस्याओं को सुना जा रहा था तभी पुलिस अधीक्षक को जानकारी मिली की दो दिव्यांग फरियादी कार्यालय के बाहर आये हुए हैं, जिसपर पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय परिसर में जाकर दोनों फरियादियों से मिले एवं उनकी समस्या के निराकरण हेतु तत्काल संबन्धित को निर्देशित किया गया।

अवध की आवाज ब्यूरो

उन्नाव। उन्नाव में पुलिस अधीक्षक उन्नाव दिनेश त्रिपाठी द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आमजन की समस्याओं को सुना जा रहा था तभी पुलिस अधीक्षक को जानकारी मिली की दो दिव्यांग फरियादी कार्यालय के बाहर आये हुए हैं, जिसपर पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय परिसर में जाकर दोनों फरियादियों से मिले एवं उनकी समस्या के निराकरण हेतु तत्काल संबन्धित को निर्देशित किया गया।

मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में उद्योग संस्थान की बैठक

अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के बी.टेक और एम.टेक छात्रों को 5 नवंबर को आयोजित 'इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट मीट' में व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान किया गया। छात्रों से बात करते हुए, विजय कुमार शर्मा (वरिष्ठ प्रबंधन, पवन इंडस्ट्रीज लिमिटेड) ने कहा कि प्रौद्योगिकी में नवाचार और विकास को बढ़ाने के लिए उद्योग और शिक्षाविदों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने लघु और मध्यम उद्योगों में इंजीनियरिंग की बुनियादी बातों पर चर्चा की और छात्रों पर प्रतिस्पर्धा के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के लिए जोर डाला। विजय कुमार ने छात्रों को उद्योग की जरूरतों के अनुसार अपने ज्ञान को नियमित रूप से अपडेट करने के लिए प्रेरित किया। स्वागत भाषण में, प्रो एम मुजम्मिल (अध्यक्ष, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग) ने उद्योग और संस्थान के बीच तालमेल के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा और उद्योग के बीच एक मजबूत सहयोग अर्थव्यवस्था को विकसित करने, नवाचार को सक्षम बनाने, शिक्षा प्रणाली में विकास और संगठन के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करने में मदद करता है। स्वागत प्रोफेसर मोहम्मद अली ने किया और कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद नासिर खान ने किया।

योगी ने पीएम के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का किया उद्घाटन, सतुआ बाबा को देंगे श्रद्धांजलि

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार की सुबह वाराणसी पहुंचे। जहां उन्होंने सबसे पहले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसी दौरान सीएम विविध आयोजनों में सम्मिलित होंगे। इसके बाद वह रविदास घाट पर जेटी लोकार्पण और निर्माण आरंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। जहां उनके साथ केंद्रीय जल परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि शुक्रवार सुबह सीएम योगी ने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पहुंच कर आठ दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। इस दौरान वह विविध आयोजनों में सम्मिलित होंगे। जहां सीएम बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में आयोजित सातवें अंतरराष्ट्रीय आदर्श ग्राम सम्मेलन में भी सीएम शामिल होंगे। दरअसल यह सम्मेलन देश में पहली बार हो रहा। जानकारी के मुताबिक इस सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों और विश्वविद्यालयों सहित 20 देशों के 800 से अधिक प्रतिभागी सम्मानित होंगे। वहीं, इसके बाद मुख्यमंत्री योगी श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन करने जाएंगे। साथ ही वह श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के त्र्यंबक भवन में आयोजित षष्ठ पीठाधीश्वर सतुआ बाबा यमुनाचार्य महाराज की श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल होंगे। जिसके बाद सीएम पं. दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में आयोजित गति शक्ति समिट में शामिल होंगे और इसके तुरंत बाद वह लखनऊ वापस लौट जाएंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनायी गयी मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती

लखनऊ। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत नवयुग कन्या महाविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग की एकलव्य संस्था के तत्वावधान में आज भारत रत्न से सम्मानित भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की 134 वी जयंती राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनायी गयी। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों को याद किया गया। इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में महाविद्यालय के विभिन्न विभागों की छात्राओं ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया ।प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस से संबंधित 50 प्रश्न पूछे गए। छात्राओं ने उत्साह पूर्वक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया। इसी क्रम में बीए प्रथम सेमेस्टर की छात्रा अर्शना चौरसिया ने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के महत्व के बारे में बताया और बीए प्रथम सेमेस्टर की छात्रा मुस्कान बाजपेई ने शिक्षा के महत्व पर कविता प्रस्तुत की। निर्णायक मंडल के सदस्यों में डॉ विनीता सिंह विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग एवं डॉ अंजुला कुमारी अर्थशास्त्र विभाग शामिल थे। प्रतियोगिता का परिणाम इस प्रकार रहारू प्रथम पुरस्कार नेहा कुमारी बीए प्रथम सेमेस्टर द्वितीय पुरस्कार लक्ष्मी शर्मा बीए पंचम सेमेस्टर तृतीय पुरस्कार प्रीति सिंह ठ.म्क प्रथम सेमेस्टर सांत्वना पुरस्कार सानिया हसन बी0एससी0 प्रथम सेमेस्टर कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की जीवनी पर प्रकाश डाला तथा उनके द्वारा दिए गए शैक्षिक योगदान के बारे में बताया। प्राचार्य ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया तथा विजेताओं को बधाई दी। शिक्षा शास्त्र विभाग

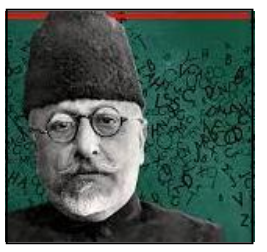

की विभागाध्यक्ष श्रीमती सुनीता सिंह के निर्देशन में श्रीमती ऐश्वर्या सिंह और नीलम के सहयोग से प्रतियोगिता सफलता पूर्वक संपन्न हुई।

यूपी में 11500 के पार पहुंची डेंगू मरीजों की संख्या

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद मरीजो की बढ़ती संख्या में ब्रेक लगता नही दिख रहा। सरकारी आकंड़ों की माने तो राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा 1 हजार 677 मरीज हैं, वही प्रयागराज में 1 हजार 543 डेंगू पॉजिटिव केस रिपोर्ट हो चुके हैं। वही अयोध्या और गाजियाबाद में भी तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही हैं। शुक्रवार को आई रिपोर्ट में अयोध्या में 690 पॉजिटिव मरीज मिले थे वही गाजियाबाद में यह संख्या 674 तक पहुंच गई हैं। शुक्रवार को एक बार फिर अस्पतालों में बुखार रोगियों की भीड़ उमड़ी। ओपीडी में सुबह से लंबी लाइन लगाकर डॉक्टर को दिखाने के लिए मरीज और तीमारदार अस्पताल पहुंचे। अस्पतालों में मरीजों को सभी सुविधाएं मुहैया होने के दावों के बीच तमाम जगह कई समस्याएं भी देखने को मिली। सिविल अस्पताल पहुंचे रिंकू शुक्ला ने बताया कि बुखार लगातार आ रहा है मेडिकल स्टोर्स 3 दिन दवा लेकर 3 दिन तक खाया है पर हाला जब तक असर रहता है तभी तक आराम लगता है थोड़ी देर बाद तक बुखार चल जाता है आज अस्पताल आए थे सोचा यहां जांच करा लेंगे पर डॉक्टर ने दवा लिखकर 5 दिन बाद आने को कहा है अभी जांच नहीं कराया। मन्ने सकता है मन में शंका है कहीं डेंगू तो नहीं है अचानक से प्लेटलेट तो लग जाए ना कम हो जाए। मास्क लगाकर राजबन्धु लोकबंधु अस्पताल पहुंचे दीपक कुमार ने बताया खांसी जुकाम बुखार सब कुछ हैं। सांस फूल रही हैं, शरीर बदन में भी दर्द हैं। चलने की हिम्मत नहीं थी पर किसी तरह अस्पताल पहुंचा हूं। डॉक्टर को दिखाया है। ढाई घंटे इंतजार करने के बाद दो पत्ता दवाई मिली है, देखों आराम मिलता हैं या नही? सिविल अस्पताल के निदेशक डॉ.आनंद ओझा ने बताया कि अस्पताल में बुखार को लेकर सभी दवाएं मौजूद हैं और मरीजों की जांच भी कराई जाए जा रही हैं। मरीजों की सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को बोला गया हैं। अगर कोई गंभीर मरीज आता हैं तो उसका भर्ती करके इलाज करते हैं।

अवध की आवाज ब्यूरो

उन्नाव। शिवा बेकरी जन सेवा केंद्र व कॉस्मेटिक सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्षा प्रतिनिधि शशांक शेखर पहुंचकर फीता काटकर दी शुभकामनाएं वही पर मौजूद पत्रकार सुरक्षा महा समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष गुड्डू मिश्रा ने डायरी पेन देकर शिष्टाचार भेंट की साथ ही साथ पत्रकार विजय सिंह को माला पहना कर सम्मान किया एवं साथ में क्राइम संवाददाता हिमांशु शुक्ला वरिष्ठ संवाददाता योगेश द्विवेदी पत्रकार विकास अवस्थी एवम् जनपद के पत्रकार साथी मौजूद रहे। वहां पर मौजूद मुनेंद्र सिंह चंदेल भोला सिंह समर सिंह चंदेल राजेंद्र सिंह चंदेल पूर्व प्रधान भदनी धीरेन्द्र सिंह राजेश सिंह विवेक लोधी मनोज गौतम अशोक गौतम द्वारिका प्रसाद भारी संख्या में लोग मौजूद रहे।

लखनऊ से लापता बहनें बरेली में मिलीं, जानिए दोनों के लापता होने के पीछे की रोचक कहानी

लखनऊ। कानपुर से लखनऊ लौट रही दो बहनों के अचानक लापता हो जाने के मामले में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने बरेली के शॉपिंग मॉल से लड़कियों को बरामद कर लिया है। दोनों बहनें अपने माता–पिता की रोक–टोक और सवाल–जवाब से परेशान होकर अपनी मर्जी से मौसी से मिलने बरेली और फिर आगे अमृतसर जाने वाली थीं। अगर पुलिस की तरफ से थोड़ी भी देरी हो जाती तो दोनों बहनें बरेली से ट्रेन पकड़कर अमृतसर चली जाती। जानकारी मुताबिक गुरु पर्व के मौके पर कानपुर गई लखनऊ के कृष्णानगर की दोनों बहनें बरेली में मॉल में घूमते मिलीं। दोनों बहनों के साथ कानपुर से इनकी दोस्त भी घर से बिना बताए चली आई थी। लखनऊ पुलिस की टीम ने इन तीनों लड़कियों को बरेली के शॉपिंग मॉल से बरामद किया। पुलिस पूछताछ में लड़कियों ने अपने लापता होने के पीछे एक रोचक कहानी बताई। लड़कियों ने बताया कि वह दोनों अपने पिता की रोक–टोक से नाराज थीं। उनके पिता उनसे सवाल–जवाब बहुत करते थे। ऐसा ही कुछ उनके साथ कानपुर से लौटते समय हुआ जब उनके पिता ने उनसे बस के अंदर का वीडियो मांग लिया। लड़कियों ने बताया

कि वे कैसरबाग से बरेली जा रही परिवहन निगम की बस में सवार हो गईं। बरेली में उन दोनों की मौसी रहती है लेकिन मौसी को बिना बताए ही वे बरेली पहुंचकर घूमने लगीं। जब लखनऊ पुलिस ने दोनों बहनों और उनकी दोस्त को बरामद किया तो यह तीनों ही लड़कियां बरेली से देर शाम ट्रेन पकड़कर अमृतसर जाने वाली थीं। अमृतसर में इनका एक अन्य रिश्तेदार रहता है, जिसके पास जाकर तीनों बहनें स्वर्ण मंदिर जाना चाह रही थी। फिलहाल लखनऊ पुलिस ने दोनों बहनों के साथ उनकी दोस्त को भी बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया है।

बंद मकान में फंदे पर लटका मिला युवक का शव

बांदा। कोतवाली इलाके में बंद मकान में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। बदबू आने पर मोहल्ले वालों ने जबलपुर में रह रही मां और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने गुरुवार सुबह मकान का दरवाजा तोड़कर शव निकाला। पुलिस का कहना है कि शव 7 दिन पुराना है। पुलिस ने शव का कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। शहर कोतवाली के गायत्री नगर मोहल्ला निवासी आशू नामदेव (19) पुत्र ब्रजबिहारी का शव कमरे के अंद रस्सी से लटका मिला। शव से दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव निकाला। जबलपुर से आई आशू की मां वर्षा नामदेव व बहन काजल ने बताया कि आशू नशे का लती था। नशे के लिए पैसा न मिलने पर वह घर में तोड़फोड़ करता था। मोहल्ले के लोग भी उससे आजिज थे। वह दो महीने पहले उसे अकेला छोड़कर जबलपुर भाई के यहां रहने चली गई थी। 7 दिन पहले आशू ने उन्हें फोन किया था और मकान बेचकर पैसा देने को कहा था। उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया था। उन्हें मोहल्ला वासियों ने घर से दुर्गंध आने की जानकारी दी। बहन काजल ने बताया कि आशंका है कि नशे में किसी से पैसा मांगने में झगड़ा हो गया होगा। उसी में उसने फंदा लगा लिया। इंस्पेक्टर श्यामबाबू शुक्ला ने बताया कि प्रथम दृष्ट्या मामला आत्महत्या का है। शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा कूटरचित आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी सहित अन्य कई दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का भण्डाफोड़

अवध की आवाज ब्यूरो

उन्नाव। जनपद उन्नाव में पुलिस सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरानजनपद उन्नाव के पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी से जानकारी पत्रकार बंधुओं को मिली,थाना दही पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा कूटरचित आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी सहित अन्य कई दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का भण्डाफोड़ करते हुए गिरोह के चार सदस्यों की गिरफ्तारी व भारी मात्रा में कूटरचित दस्तावेज व कूट रचितसामान की बरामदगी के संदर्भ में दी गई बाइट मे बताया थाना दही व स्वाट टीम प्रभारी द्वारा 4 लोगोंको गिरफ्तार किया गया है जिनके द्वारा कूट रचित आधार कार्ड आईडी कार्ड जन्म प्रमाण मृत्यु प्रमाणपत्र आदिबनाए जाते थे फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड फर्जी तरीके से बनाए जाते थे। इनके द्वारा जन सेवा केंद्र चलाया जाता था जन सेवा केंद्र में पहले फर्जी तरीके से फर्जी वोटर कार्ड आईडी एक टेंडर के द्वारा बीएसएनल टाइजफ इसमें शामिल है उनको बुलाया जाता था। बीएसएनल की साइट पर जाकर आधार कार्ड बनाया जाता था इसमें कुल 56 वोटर आईडी कार्ड बरामद हुए जब उसका परीक्षण कराया गया 6आधार कार्ड है उस स्थान पर रहने वालों का पता गलत दिया गया इस तरीके से कूट रचित तरीके से आधार कार्ड वगैरा गलत तरीके से बनाए जाते थे।

बीकेटी में साधन सहकारी समिति पर खाद नहीं

लखनऊ। इस समय गेहूं और आलू की बुआई चल रही है। साधान सहकारी समितियों से खाद नदारद है। जिससे खाद्य उपलब्धा नहीं होने के चलते किसान परेशान हैं। पहले तो खरीफ की फसल में धान और दलहनी फसलों का असमय हुई भारी बारिश से नुकसान उठाना पड़ा है। अब रबी की फसलों की बुआई में सहकारी समिति में खाद नहीं होने से गेहूं और आलू की बुआई भी प्रभावित हो रही है। इससे किसानों को इस बार भी फसल में नुकसान उठाना पड़ेगा, इस बात से किसान परेशान हैं। बता दें कि रबी की फसलों की बुआई का समय चल रहा है। किसान मुख्य रूप से गेहूं, आलू सहित तिलहन फसलों की बुआई करते हैं। राजधानी से सटे ग्रामीण क्षेत्र बख्शी का तालाब किसान फसलों की बुआई के लिए तैयार है, लेकिन साधन सहकारी समितियों में खाद नदारद है। सहकारी समितियों में खाद नहीं होने से किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। जिसके चलते क्षेत्र के नगर चौगावां साधन सहकारी समिति में खाद को लेकर बवाल मच चुका है। खाद आपूर्ति के जहां तमाम सरकारी दावे खोखले साबित हो रहे हैं, वहीं किसानों के लिए विषम समस्या है। इतना ही नहीं, बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला के पैतृक गांव पहाड़पुर में स्थित साधन सहकारी समिति पहाड़पुर में मौजूदा समय में खाद उपलब्ध नहीं है। जिससे किसान परेशान हैं। खेत बुआई के लिए तैयार है, लेकिन खाद नहीं होने से फसल की बुआई में देरी हो रही है। चंद्रभान गुप्त कृषि महाविद्यालय के कृषि विशेषज्ञ डॉ. सत्येन्द्र सिंह ने बताया कि जहां पिछले दिनों असमय हुई बरसात से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं अब रबी की फसलों की बुआई में गेहूं और आलू की सयय से बुआई करने से लाभ प्राप्त हो सकता है। फसलों की बुआई का सही समय चल रहा है। ऐसे में यदि बुआई में देरी हो जाती है तो फसलों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

जल शक्ति अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

अवध की आवाज ब्यूरो

सिधौली–सीतापुर। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत लोगों में जल का महत्व, जल की उपलब्धता, वर्षा जल का संरक्षण, मानव जीवन एवं फसलों में जल के सदुपयोग की तकनीक, भूगर्भ जल रिचार्ज की तकनीक आदि की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दो एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें जनपद के किसानों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रभारी वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष अमरनाथ सिंह ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में केंद्र के वैज्ञानिक डॉ विनोद कुमार सिंह ने जल की उपलब्धता, वर्षा जल का संरक्षण, मानव जीवन एवं फसलों में जल के सदुपयोग की तकनीक, भूगर्भ जल रिचार्ज की तकनीक आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। डा0 सिंह ने अपने अपने संबोधन में कहा कि लोगों के ध्यान ना देने के कारण आज बहुत से क्षेत्रों में पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है और यह समस्या दिनोंदिन बढ़ती ही जानी है। यदि हम लोग वर्षा जल के संरक्षण पर ध्यान नहीं देंगे एवं गलत तरीके से अंधाधुंध भूगर्भ जल का दोहन करेंगे तो आने वाले समय में भारी जल संकट का सामना करना पड़ेगा इसलिए हम लोगों को कल के लिए जल की व्यवस्था करना पड़ेगा अन्यथा भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकट से गुजारना पड़ेगा। गृह विज्ञान विशेषज्ञ ऋचा सिंह ने मानव जीवन में जल के महत्व पर जानकारी उपलब्ध कराई तथा मृदा विज्ञान विशेषज्ञ डा0 उमेश कुमार सिंह ने फसलों में सिंचाई की उन्नत तकनीक की विस्तृत जानकारी प्रदान किया। कार्यक्रम के अन्त में किसानों की समस्याओं का समाधान किया गया।

सम्पादकीय

चीन का मॉडल भारत के अनुकूल नहीं

मध्य चीन में स्थित फॉक्सकॉन की फैक्ट्री से भयावह कहानियां सामने आ रही हैं। यह कंपनी एप्पल आईफोन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है. मध्य चीन में फिर से कोरोना फैल रहा है. रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि काम करने वाले लोग फैक्ट्री से भाग रहे हैं। कोविड संक्रमण रोकने के नाम पर कड़े नियम लागू किये गये हैं और लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, लेकिन कामगारों की शिकायत है कि अकेले रखे गये लोगों को खाने–पीने की वस्तुओं की आपूर्ति कम हो रही है तथा चिकित्सा व्यवस्था भी ठीक नहीं है।

इस संयंत्र परिसर में लगभग दो लाख लोग रहते हैं। उन्हें पहले से ही कई परेशानियां थीं, जो अब और बढ़ गयी हैं। भाग रहे कामगारों को वापस बुलाने की कोशिश हो रही है, पर वे बोनस प्रस्तावों को आम तौर पर ठुकरा दे रहे हैं। कथित रूप से परिसर में फिल्माये गये एक वीडियो में दिखाया गया है कि एक कमरे में अलग रहे गये कामगारों की मौत हो गयी है, जबकि फॉक्सकॉन का कहना है कि वहां कोई मौत नहीं हुई है। अनेक मुश्किलों से जूझते कामगारों की ऐसी कई खबरें आयी हैं। वे खबरें भारत के लिए अहम हैं क्योंकि फॉक्सकॉन और कुछ अन्य कंपनियां 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के अंतर्गत दिये गये प्रस्तावों से आकर्षित होकर भारत में संयंत्र लगा रही हैं। वेदांता और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उपक्रम गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित हो रहा है, जहां एक सेमीकंडक्टर फैब इकाई, एक डिस्प्ले फैब इकाई तथा एक सेमीकंडक्टर एसेंबली व टेस्टिंग इकाई लगायी जायेगी। वेदांता ने कहा है कि इस परियोजना में कुल डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा तथा इससे करीब एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यह सही है कि भारत को निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए त्वरित कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन यहां यह सवाल भी उठता है कि क्या भारत को भी चीन की तरह वैसी बड़ी–बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित करनी चाहिए, जहां मामूली वेतन की निम्न स्तर की नौकरियां हों। ऐसी फैक्ट्रियों में ज्यादातर काम असेंबली का होता है। मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के मामले में चीन का खराब रिकॉर्ड रहा है। मजदूर संगठनों का अस्तित्व न के बराबर है और स्थानीय प्रशासन कारोबारी मांगों पर ही अधिक ध्यान देता है, ताकि अधिक निवेश आ सके। इसी कारण चीन निम्न स्तरीय मैन्युफैक्चरिंग नौकरियों के लिए आकर्षक गंतव्य बना हुआ है. ।वहां नौकरी खोजने वालों की बहुत बड़ी संख्या है, इसका मतलब है कम वेतन, कामगारों की कमजोर सुरक्षा तथा मजदूरों से जबरदस्ती काम लेना. यही कारण है कि कामगारों को वहीं रहना पड़ता है, जहां कंपनी चाहती है. आम तौर पर कमरे छोटे–छोटे होते हैं तथा मामूली सुविधाएं मिलती हैं। उन्हें लगातार काम करना पड़ता है ऐसे में कई कामगार आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भारत को कंपनियों को बुलाने से पहले रोजगार सृजन के इस मॉडल का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए. यह मॉडल भारत जैसे देश में एकदम अनजानी व्यवस्था को स्थापित करेगा, जहां छोटे और मझोले उद्यम अर्थव्यवस्था में भारी योगदान करते हैं। यह बात भी सही है कि छोटे और मझोले उद्यम हमेशा अच्छे रोजगार प्रदाता या गुणवत्तापूर्ण उत्पादक नहीं होते, पर आर्थिक वृद्धि का विस्तारित मॉडल उस मॉडल से बिल्कुल अलग है, जिसमें बड़े उद्योगों, बड़ी फैक्ट्रियों और ऊपर से आती समझ से विकास निर्देशित होता है, जो तुरंत रोजगार देने का वादा तो करता है, पर आम तौर पर दीर्घकालिक परेशानियां ही पैदा करता है। अमेरिका में विस्कॉन्सिन में फॉक्सकॉन का उपक्रम नहीं लग सका और मिल्वाकी में एक सरकारी रिपोर्ट में कंपनी के कामगार सुरक्षा रिकॉर्ड पर सवाल उठाये गये हैं. इस संदर्भ में बड़े उद्योगों को दी जाने वाली छूट पर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की कुछ आलोचनाएं बहुत प्रासंगिक हैं। उन्होंने सही ही रेखांकित किया है कि उत्पादन से संबंधित इंसेंटिव योजनाओं का इस पहलू से ठीक से विश्लेषण नहीं किया गया है कि ये रोजगार सृजन का एक रास्ता हैं। भले ही चीन में खास तरह की बहुत मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, लेकिन वह देश उच्च स्तर का नवोन्मेषी देश नहीं बन सका है। उसकी छवि एक सीमित सस्ते उत्पादक देश की ही है. कारोबार से होने वाले लाभ का बड़ा हिस्सा चिप डिजाइनर और ब्रांड के पास चला जाता है तथा मूल्य शृंखला का मामूली निचला हिस्सा चीन के हिस्से में आता है। अनेक अध्ययन इंगित करते हैं कि आइफोन जैसे महंगे उत्पाद की कीमत का लगभग चार–पांच प्रतिशत ही चीन को मिल पाता है। अब चीन में भी निर्माण खर्च में वृद्धि हो रही है और यह भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि वह चीन का सतही संस्करण बन जाए. एक अध्ययन में बताया गया है कि चीन के हिस्से में कम वेतन की नौकरियां आती हैं, जबकि मुनाफा अन्य देशों को चला जाता है. वह मैन्युफैक्चरिंग का वैसा मुकाम नहीं है, जहां भारत पहुंचना पसंद करेगा।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विस्तार

देवेंद्रराज सुथार

हर वर्ष 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है. इसका उद्देश्य समाज में विज्ञान की भूमिका को रेखांकित कर जन सामान्य के बीच विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के युवा वैज्ञानिकों के लिए आदर्श वाक्य रहा है– इनोवेट, पेटेंट, प्रोड्यूस एंड प्रॉस्पर। ये चार कदम हमारे देश को तेजी से विकास की ओर ले जायेंगे।

उम्मीद है कि हमारे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक अपनी लगन से नयी सहस्राब्दी की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की चुनौतियों का सामना करने और दुनिया में अपनी छाप छोड़ने में सफल होंगे. वह दिन दूर नहीं जब दुनिया हमें पूर्व की भांति धर्म जगत का गुरु कहने के साथ विज्ञान एवं तकनीकी का भी गुरु कहेगी और डॉ कलाम का भारत को अग्रणी राष्ट्रों की श्रेणी में लाने का सपना साकार हो सकेगा. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भारतीय परिप्रेक्ष्य को शब्दों में व्यक्त करना अत्यंत कठिन है. भारत ने स्वतंत्रता के 75 वर्षों में जैसा प्रदर्शन किया है, वह निश्चित ही प्रेरणादायी है. पर विकट प्रश्न यह है कि किस प्रकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को शिक्षित, स्वस्थ तथा समृद्ध बनाया जाए? इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प शक्ति से विज्ञान–प्रौद्योगिकी का सुनियोजित प्रयोग कर गरीबी, अशिक्षा का समूल नाश कर सकते हैं और ज्ञान के उस मानदंड को पुनः प्राप्त कर सकते हैं जिससे भारत विकसित तथा समृद्ध राष्ट्र बने. नये आविष्कारों को व्यवहार में कैसे लाया जाए, इस पर गहन अध्ययन जरूरी है. इक्कीसवीं सदी तकनीकी क्रांति की है और देश की ताकत सूचना क्रांति पर निर्भर है. विज्ञान से आम आदमी के जीवन में कैसे सुधार आ सकता है इस पर व्यापक विमर्श होना चाहिए. देश की दो–तिहाई आबादी गांवों में रहती है. ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन वैज्ञानिक तंत्र के माध्यम से ऊपर उठाया जा सकता है। बढ़ती आबादी को जनोपयोगी बनाने में विज्ञान अपनी भूमिका निभा सकता है. हम अभी तक आम आदमी में वैज्ञानिक चेतना का विकास नहीं कर पाये हैं. यदि हम भारत को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें शोध पर जीडीपी बढ़ानी होगी. स्कूलों में मध्याह्न भोजन की तरह विज्ञान के उपकरण भी उपलब्ध कराने होंगे। प्रयोगशालाओं पर ध्यान देना होगा. वैज्ञानिक प्रतिभाओं को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करा पलायन रोकना होगा। विज्ञान की तरफ छात्र आकर्षित हों इसके लिए बेहतर वातावरण बनाना होगा. छात्रों को छात्रवृत्ति का अधिकाधिक लाभ मिले यह सुनिश्चित करना होगा. यहां हम यूरोप, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश से बहुत कुछ सीख सकते हैं। शिक्षा सस्ती और सुलभ हो, यह सुनिश्चित करना सरकारों का उत्तरदायित्व है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा मुनाफा कमाने का कारोबार नहीं है। वर्ष 2017 में आंध्र प्रदेश सरकार ने मेडिकल पाठ्यक्रम के शुल्क में सात गुना बढ़ोतरी कर दी थी। उस आदेश को निरस्त करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने निजी मेडिकल कॉलेजों को वसूली गयी फीस छात्रों को लौटाने को कहा है. आंध्र प्रदेश सरकार के उक्त आदेश को राज्य के उच्च न्यायालय ने सितंबर, 2019 में ही रद्द कर दिया था, जिसे एक निजी कॉलेज ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता कॉलेज और आंध्र प्रदेश सरकार पर अदालत ने सुनवाई के खर्च के रूप में पांच लाख रुपया जमा कराने को भी कहा है। साल 2017 में राज्य के कॉलेजों में सालाना फीस 24 लाख रुपया कर दी गयी थी, जिसे उच्च और उच्चतम न्यायालय ने पूरी तरह अनुचित बताया है.हमारे देश में मेडिकल सीटों की बहुत कमी है. कॉलेज अन्य मदों के नाम पर भी भारी रकम वसूलते हैं। चयनित छात्रों को इसके लिए कर्ज लेना पड़ता है और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया है कि ऐसे कर्ज में बहुत अधिक ब्याज भी देना पड़ता है। जब वे पाठ्यक्रम पूरा कर डॉक्टर बन जाते हैं, तो उनकी प्राथमिकता कर्ज चुकाना होती है. निजी क्लीनिकों और अस्पतालों में महंगे उपचार का यह एक बड़ा कारण है। भारी फीस के कारण कई छात्र चीन, यूक्रेन, रूस, मध्य एशिया के देशों आदि में प्रवेश लेने को मजबूर होते हैं, जहां पढ़ाई सस्ती पड़ती है. बाहर के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। हाल में केंद्र सरकार ने एक सराहनीय फैसले में निजी संस्थानों को निर्देश दिया है कि उनके यहां उपलब्ध सीटों में से आधी सीटों पर शुल्क सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों को नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए जमीन और अन्य संसाधन मुहैया कराने का भी अनुरोध किया है.भारी फीस की समस्या अन्य तकनीकी और प्रबंधन पाठ्यक्रमों के साथ भी है. निजी शिक्षण संस्थानों में सामान्य पाठ्यक्रम भी बहुत महंगे हैं. केंद्र और राज्य सरकारों को निजी संस्थानों पर निगरानी बढ़ानी चाहिए तथा शुल्क संरचना एवं गुणवत्ता की समीक्षा प्रक्रिया को कठोर बनाना चाहिए. स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक भारी शुल्क पर लंबे समय से चर्चा होती रही है. महंगी शिक्षा आबादी के बड़े हिस्से को बहिष्कृत भी करती है। भारत के उत्तरोत्तर विकास को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा का विस्तार आवश्यक है।

चुनावी बॉन्ड की पारदर्शिता पर सवाल

हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनावों से ठीक पहले केंद्र की एनडीए सरकार ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए चुनावी बॉन्ड योजना–2018 में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय ने 7 नवंबर को एक अधिसूचना जारी कर बताया है कि विधानसभा चुनावों के वर्ष में बॉन्ड की ब्रिक्री के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय देने के संशोधन को मंजूरी दी गई है।

गौरतलब है कि 2017 में एनडीए सरकार ने चुनावी चंदे के लिए चुनावी बॉन्ड लाने का ऐलान किया था और 2018 में यह योजना लागू भी हो गई थी। इसके तहत साल में चार बार अप्रैल, जनवरी, जुलाई और अक्टूबर महीने के पहले दस दिनों तक चुनावी बॉन्ड खरीदने का नियम तय हुआ था। आम आदमी से लेकर बड़े उद्योगपति और व्यावसायिक घराने या कंपनियां चुनावी बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीद सकते हैं। यह एक तरह का पैसे के रूप में वचन है जो आप किसी राजनैतिक दल को चंदे के रूप में देते हैं। इससे पहले राजनैतिक दलों को कोई व्यक्ति या औद्योगिक घराने जो भी चंदा देते थे, उसका खुलासा उन्हें करना पड़ता था और राजनैतिक दलों को भी घोषित करना पड़ता था कि उन्हें किससे, कितना चंदा मिला। लेकिन मोदी सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना में बॉन्ड के खरीदार की पहचान जारी नहीं होती। सरकार का तर्क है कि यह चुनावी चंदे में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और लोगों को राजनैतिक दलों के दबाव से मुक्त रखेगा। हालांकि यह तर्क दिल के बहलाने के लिए ही काफी है। हम राजनीति का वह दौर देख रहे हैं, जब डिजीटल तकनीकी का इस्तेमाल लोगों की जासूसी के लिए हो रहा है। कब, कहां, किसके मोबाइल या कम्प्यूटर पर किसी सॉफ्टवेयर के जरिए निगरानी रखी जाएगी, कहा नहीं जा सकता। मामूली नजर आने वाली चिप से किसी व्यक्ति के बैंक खाते से लेकर उसके पहचान पत्र और पसंद, नापसंद, स्वास्थ्य की स्थिति और आवाजाही का पता क्षणों में लगाया जा सकता है। तब किस व्यक्ति या संस्था या कार्पोरेट घराने ने एसबीआई की किस शाखा से कितने का चुनावी बॉन्ड खरीदा और किस राजनैतिक दल ने उसे भुनाया, यह पता लगाना कोई कठिन बात नहीं है।

इसलिए यह बात बेमानी है कि चुनावी बॉन्ड से किसी किस्म की पारदर्शिता आ रही है। बल्कि यह डर हमेशा बना रहेगा कि सत्ताधारी दल लोगों पर चुनावी बॉन्ड खरीदने का दबाव बनाए, ताकि उसका कोष भरता जाए। चुनावी बॉन्ड इन्हीं सब कारणों से विवादों में आए और इसके खिलाफ याचिका भी दायर हुई थीं। पिछले महीने ही एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स यानी एडीआर की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिस पर एडीआर की ओर से बॉन्ड पर रोक की मांग करते हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि इनका उपयोग शेल कंपनियां कालेधन को सफेद बनाने में कर रही हैं। बॉन्ड कौन खरीद रहा है, इसकी जानकारी सिर्फ सरकार को होती है। चुनाव आयोग तक इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं ले सकता है। ये राजनीतिक दल को रिश्वत देने का एक तरीका है। जबकि केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि चुनावी बॉन्ड राजनीतिक चंदे का एक पारदर्शी तरीका है। इससे काला धन मिलना संभव नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले की विस्तार से सुनवाई के लिए 6 दिसंबर की तारीख तय की थी, मगर उससे पहले केंद्र सरकार ने एक नया संशोधन इसमें पेश कर दिया। 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना जब लागू हुई थी, तो इसके मूल स्वरूप में प्रावधान था कि लोकसभा चुनाव वाले वर्ष में बॉन्ड बिक्री के लिए 30 अतिरिक्त दिन प्रदान किए जाएंगे, अब नए संशोधन में बिक्री के लिए 15 दिन और जोड़ दिए गए हैं। देश में लगभग हर साल किसी न किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होते ही हैं, तो नए संशोधन के मुताबिक हर साल इस बॉन्ड की बिक्री के लिए 15 दिन और बढ़ जाएंगे। निश्चित तौर पर यह फैसला भाजपा को फायदा पहुंचाने के मकसद से लिया गया दिख रहा है। अन्यथा ऐन चुनाव के पहले इस तरह का संशोधन नहीं किया जाता। यह ध्यान देने वाली बात है कि संशोधन 7 तारीख को हुआ और 9 तारीख से चुनावी बॉन्ड एक हफ्ते के लिए एसबीआई की शाखाओं में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे, ऐसी घोषणा भी सरकार ने कर दी। जबकि अभी हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों के लिए आचार संहिता लागू है। जिस फैसले को आचार संहिता के दौरान लिया गया और जो मुद्दा अदालत में विचाराधीन है, क्या उस पर कोई संशोधन सरकार को करना चाहिए, इन दोनों बिंदुओं पर अगर विचार करें तो इसमें सरासर चालाकी से की जा रही बेईमानी नजर आएगी। इसलिए इस फैसले पर सवाल उठने शुरु हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय सचिव ई.ए.एस. सरमा ने इसे अनुचित कदम बताते हुए चुनाव आयोग से चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं पूर्व चुनाव आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ति ने सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए सुझाव दिया है कि हमें एक राष्ट्रीय चुनाव कोष बनाकर चुनावों में सार्वजनिक फंडिंग करना चाहिए, जिसमें चंदे पर 100 फीसदी टैक्स छूट हो। ताकि चंदा देने वालों और राजनीतिक दलों के बीच कोई गठजोड़ न हो सके। सरकार अगर वाकई चुनावों में पारदर्शिता और ईमानदारी से वित्तप्रबंध करना चाहती है, तो उसे इस विषय के जानकार लोगों और अन्य राजनैतिक दलों से परामर्श कर कोई तर्कसम्मत फैसला लेना चाहिए, जिससे अनावश्यक विवाद खड़े न हों। अभी जिस तरह चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की बिक्री के लिए दिन बढ़ाने का फैसला लिया गया है, वह सीधे नीयत पर सवाल उठाता है। इससे भाजपा पर तो उंगलियां उठ ही रही हैं, केंद्र सरकार की छवि भी दांव पर लग रही है, जो अच्छी बात नहीं है।

हर मोर्चे पर चीन की जमकर बैंड बजा रहा है भारत! 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' के जवाब में स्ट्रैटेजिक रूप से अहम 'नेकलेस ऑफ डायमंड्स'

हर गुजरते दिन के साथ चीन भारत के लिए और भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है। चीन ने रणनीतिक तरीके से भारत को घेरना भी शुरू कर दिया है। चीन ने हाल के कुछ सालों में नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाकर भारत के खिलाफ स्ट्रैजिक प्लानिंग में लगा है। विशेषज्ञों ने उसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का का नाम दिया है। आपको ये लगता होगा कि चीन हमेशा अपनी सीमा से आगे बढ़कर बॉर्डर वाले इलाकों के जरिये भारत में कब्जा जमाना जमाना चाहता है। लेकिन ये अकेला ऐसा इलाका नहीं है जहां से चीन भारत को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन ये समझना चीन को भारी पड़ सकता है कि भारत इस मामले पर केवल हाथ पर हाथ धडडे बैठा है। भारत ने भी चीन को काउंटर करने के लिए नेकलस ऑफ डायमंड नाम की एक स्ट्रैटर्जी बनाई है।

न्यूटन का गति का तीसरा नियम कहता है कि श्प्रत्येक क्रिया के लिए, एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती हैश। इसी प्रकार भारत की तैयारियों के बारे में बात करने से पहले आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि चीन आखिर कर क्या रहा है? दरअसल, बीते कुछ सालों में चीन ने भारत के पड़ोसियों के कई महत्वपूर्ण पोर्ट्स को अपने कब्जे में कर लिया है। चाहे वो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो या श्रीलंका का हंबनटोटा पोर्ट। चीन भारत के आस–पास के देशों में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ऑयल रिफाइनरी और हाई स्पीड केबल नेटवर्क स्थापित कर रहा है। चीन इस वक्त अपने महत्वकांक्षी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के अंदर चीन से लंदन और उर्जबेकिस्तान, तुर्कमेकिस्तान और पाकिस्तान से गुजरती हुई एक और रेल लाइन बना रहा है जो ईरान में जाकर खत्म होती है। जियो पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि जिसके पास इंडियन ओसियन में कंट्रोल है, उसके पास पूरे एशिया का कंट्रोल है। इंडियन ओसियन से इस वक्त दुनियाभर का 80 फीसदी ऑयल ट्रेड होता है। यहां पर कुछ ऐसे स्ट्रेटिज प्लाइंट्स हैं जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका के हंबनटोटा, बांग्लादेश के चिटगोंग पोर्ट, म्यांमार का क्यौकप्यू पोर्ट, मालदीव के फेयधूफिनोल्हु द्वीप को चीन ने अपना बेस बनाया। भारत को घेरने की इस नीति को चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम देता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति उसकी उसी सिल्क रूट का हिस्सा है जिसे वो बेल्ट एंड रोड एनिसिएटिव का नाम देता है।

<u>भारत का नेकलेस ऑफ डायमंड</u>

भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा रणनीति के लिए मोजाबिंक चौनल समेत दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर, चीन के भारी निवेश वाले पूर्वी अफ्रीकी तट को बेहद अहम मानता है। विश्लेषकों का मानना है कि ये अभ्यास हिंद महासागर में पूर्वी अफ्रीकी देशों और द्वीपीय देशों के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में हिंद महासागर भारत और चीन के बीच टकराव का नया केंद्र बनता जा रहा है। भारत ने चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति को मात देने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड नीति को मजबूत करना शुरू कर दिया है।

<u>क्या है पूरी स्ट्रैटर्जी?</u>

भारत ने हाल के दिनों में चीन को काउंटर करने के लिए गुपचुप तरीके से कई कदम उठाए हैं। जिसमें प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का काफी रोल रहा है। भारत की ये योजना जमीनी स्तर पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जिसका सीधा उदाहरण मॉरीशस में गुप्त तरीके से बन रहा भारत का मिलिट्री बेस है। मॉरीशस के अगलेगा द्वीप पर भारत के गुप्त सैन्य अड्डे की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। इस आईलैंड की नई सैटेलाइट इमेज जारी हुई है जिससे पता चलता है कि भारतीय नौसेना के च–8प सबमरीन हंटिंग विमान को रखने के लिए आईलैंड पर हैंगर का निर्माण, नए बने रनवे के बगल में हो रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर एयरोप्ट पर चीन की मौजूदगी को काउंटर करने के लिए भारत ने ओमान में एक बेस सेट–अप किया है। डैकम पोर्ट से भारत का महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल ट्रेड होता है। इसके अलावा ये पोर्ट अरेबियन सी और गल्फ ईडन दोनों पर ही अपनी नजर रखता है। जो ओमान के साथ भारत के अच्छे रिश्तों की वजह से संभव हो पाया है। भारत इंडोनेशिया के साथ सबांग बंदरगाह प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है। अफ्रीका में जिबूती, पश्चिम एशिया में ओमान के टुकम बंदरगाह पर सैन्य गतिविधि के लिए भारत को अनुमति प्राप्त है। चीन के पड़ोसी देशों में जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के साथ भारत के सैन्य समझौते हैं। जिसके अंतर्गत भारतीय नौसेना को इन देशों के बंदरगाहों पर तेल भरवाने मरम्मत करवाने और हथियार जुटाकर आगे बढ़ने का अधिकार है। – अभिनय आकाश

भारतीय संस्कृति का वाहक है हमारे देश का जनजाति समाज

भारत भूमि का एक बड़ा हिस्सा वनों एवं जंगलों से आच्छादित है। भारतीय नागरिकों को प्रकृति का यह एक अनोखा उपहार माना जा सकता है। इन वनों एवं जंगलों की देखभाल मुख्य रूप से जनजाति समाज द्वारा की जाती रही है। जनजाति समाज की विकास यात्रा अपनी भूख मिटाने एवं अपने को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से केवल वनों के इर्द गिर्द चलती रहती है। वास्तविक अर्थों में इसीलिए जनजाति समाज को धरतीपुत्र भी कहा जाता है। प्राचीन काल से केवल प्रकृति ही जनजाति समाज की सम्पत्ति मानी जाती रही है, जिसके माध्यम से उनकी सामाजिक, आर्थिक एंव पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि अनादि काल से जनजाति संस्कृति व वनों का चोली दामन का साथ रहा है और जनजाति समाज का निवास क्षेत्र वन ही रहे हैं। इस संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि वनों ने ही जनजातीय जीवन एंव संस्कृति के उद्भव, विकास तथा संरक्षण में अपनी आधारभूत भूमिका अदा की है। भील वनवासियों का जीवन भी वनों पर ही आश्रित रहता आया है। जनजाति समाज अपनी आजीविका के लिए वनों में उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते रहे हैं।

भारतीय वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पतियों, पेड़ों एवं उत्पादित वस्तुओं में शामिल रहे हैं बबूल, बेर, चन्दन, धोक, धामन, धावड़ा, गुदी, हल्दू, इमली, जामुन, कजरी, खेजड़ी, खेड़ा, कुमटा, महुआ, नीम, पीपल, सागवान, आम, मुमटा, सालर, बानोटीया, गुलर, बांस, अरीठा, आंवला, गोंद, खेर, केलडी, कडैया, आवर, सेलाई वृक्षों से करा, कत्था, लाख, मौम, धोली व काली मुसली, शहद, आदि। इनमें से कई वनस्पतियों की तो औषधीय उपयोगिता है। कुछ जड़ी बूटियों जैसे आंवला का बीज, हेतडी, आमेदा, आक, करनीया, ब्राह्मी, बोहडा, रोंजडा, भोग पत्तियां, धतुरा बीज, हड, भुजा, कनकी बीज, मेंण, अमरा, कोली, कादां, पडूला, गीगचा, इत्यादि का उपयोग रोगों के निवारण के लिए किया जाता रहा है। आमेदा के बीजों को पीसकर खाने से दस्त बंद हो जाते हैं। अरण्डी के तेल से मालिश एवं पत्तों को गर्म करके कमर में बांधने से दर्द कम हो जाता है। बुखार को ठीक करने के लिए कड़ा वृक्ष के बीजों को पीस कर पीते हैं। जोड़ों में दर्द ठीक करने के लिए ग्वार व सैजने के गोंद का उपयोग करते हैं। फोड़े फुन्सियों एवं चर्म रोग को ठीक करने के लिए नीम के पत्तों को उबालकर पीते हैं। इसके अलावा तुलसी, लौंग, सोठ, पीपल, काली मिर्च का उपयोग बुखार एवं जुखाम ठीक करने के लिए किया जाता है। शुरुआती दौर में तो जनजाति समाज उक्त वर्णित वनस्पतियों एवं उत्पादों का उपयोग केवल स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही करते रहे हैं परंतु हाल ही के समय में इन वनस्पतियों का उपयोग व्यावसायिक रूप से भी किया जाने लगा है। व्यावसायिक रूप से किए जाने वाले उपयोग का लाभ जनजाति समाज को न मिलकर इसका पूरा लाभ समाज के अन्य वर्गों के लोग ले रहे हैं। उक्त वनस्पतियों एवं उत्पादों का व्यावसायिक उपयोग करने के बाद से ही प्रकृति का दोहन करने के स्थान पर शोषण किया जाने लगा है क्योंकि कई उद्योगों द्वारा उक्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाने लगा है। इससे ध्यान में आता है कि जनजाति समाज द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने के उद्देश्य से अपनी भूमिका का निर्वहन तो बहुत सफल तरीके से किया जाता रहा है परंतु अर्थव्यवस्था के विकास का लाभ जनजातियों तक सही मात्रा में पहुंच नहीं सका है।

हालांकि भारत में प्राचीन काल से ही जनजाति समाज जंगलों में अपना जीवन यापन करता रहा है और वनोपज (जैसे मध्य प्रदेश में तेन्दु पत्ता को एकत्रित करना) को एकत्रित करता रहा है परंतु अब धीरे–धीरे अपने आप को यह समाज कृषि कार्य एवं पशुपालन जैसे अन्य कार्यों में भी संलग्न करने लगा है। जनजाति समाज ने बिना किसी भय के सघन वनों में जंगली जानवरों व प्राकृतिक आपदाओं से लड़ते हुए अपने जीवन को संघर्षमय बनाया है। जनजाति समाज ने कृषि कार्य के लिए सर्वप्रथम जंगलों को काटकर जलाया। भूमि साफ कर इसे कृषि योग्य बनाया और पशुपालन को प्रोत्साहन दिया। विकास की धारा में आगे बढ़ते हुए धीरे–धीरे विभिन्न गांवों एवं कस्बों का निर्माण किया। आज भी जनजाति समाज की अधिकांश जनसंख्या दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती है। इन इलाकों में संचार माध्यमों का अभाव है। हालांकि धीरे–धीरे अब सभी प्रकार की सुविधाएं इन सुदूर इलाकों में भी पहुंचाई जा रही हैं। परंतु, अभी भी जनजातीय समाज कृषि सम्बन्धी उन्नत विधियों से अनभिज्ञ है। सिंचाई साधनों का अभाव एवं उपजाऊ भूमि की कमी के कारण ये लोग परम्परागत कृषि व्यवस्था को अपनाते रहे हैं और इनकी उत्पादकता बहुत कम है।

जनजाति समाज ने वनों के सहारे अपनी संस्कृति को विकसित किया। घने जंगलों में विचरण करते हुए उन्होंने जंगली जानवरों शेर, भालु, सुअर, गेंडे, सर्प, बिच्छु आदि से बचने के लिए आखेट का सहारा लिया। वनों एवं पहाड़ियों के आन्तरिक भागों में रहते हुए भील समाज शिकार करके अपनी आजीविका चलाता रहा है। भील समाज जंगलों में झूम पद्धति से खेती, पशुपालन, एवं आखेट कर अपने परिवार का पालन पोषण करते रहे हैं।

घने जंगलों में जनजाति समाज को प्रकृति द्वारा, स्वछंद वातावरण, स्वच्छ जल, नदियां, नाले, झरने, पशु पक्षियों का कोलाहल, सीमित तापमान, हरियाली, आर्द्रता, समय पर वर्षा, मिटटी कटाव से रोक, आंधी एंव तूफानों से रक्षा, प्राकृतिक खाद, बाढ़ पर नियंत्रण, वन्य प्राणियों का शिकार व मनोरंजन इत्यादि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कराया जाता रहा है। इसी के चलते जनजाति समाज घने जंगलों में भी बहुत संतोष एवं प्रसन्नता के साथ रहता है।

जनजाति समाज आज भी भारतीय संस्कृति का वाहक माना जाता है क्योंकि यह समाज सनातन हिंदू संस्कृति का पूरे अनुशासन के साथ पालन करता पाया जाता है। जनजाति समाज आज भी आधुनिक चमक दमक से अपने आप को बचाए हुए है। इसके विपरीत शहरों में रहने वाला समाज समय–समय पर भारतीय परम्पराओं में अपनी सुविधानुसार परिवर्तन करता रहता है।

हाल ही के समय में अत्यधिक आर्थिक महत्वकांक्षा के चलते वनों का अदूरदर्शितापूर्ण ढंग से शोषण किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष 110 लाख हैक्टर भूमि के वन नष्ट किये जा रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार प्रत्येक देश में उपलब्ध भूमि के लगभग 33 प्रतिशत भाग पर वन होना आवश्यक है। यदि वनों का इस प्रकार कटाव होता रहेगा तो जनजाति समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है।

भारत द्वारा इस संदर्भ में कई प्रयास किए जा रहे हैं। देश में वनों के कटाव को रोकने के लिए वर्ष 2015 एवं 2017 के बीच देश में पेड़ एवं जंगल के दायरे में 8 लाख हेक्टेयर भूमि की वृद्धि दर्ज की है। साथ ही, भारत ने वर्ष 2030 तक 2.10 करोड़ हेक्टेयर जमीन को उपजाऊ बनाने के लक्ष्य को बढ़ाकर 2.60 करोड़ हेक्टेयर कर दिया है ताकि वनों के कटाव को रोका जा सके।

भारत में सम्पन्न हुई वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 10.43 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। जनजाति समाज को देश के आर्थिक विकास में शामिल करने के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि इस समाज की कठिन जीवनशैली को कुछ हद्द तक आसान बनाया जा सके।

–प्रह्लाद सबनानी

फाइलेरिया रोगियों के क्लस्टर फोरम के सदस्यों की बैठक हुई आयोजित

अवध की आवाज ब्यूरो

लखनऊ। स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में स्वयंसेवी संस्था सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च(सीफार) के सहयोग से फाइलेरिया रोगियों के क्लस्टर फोरम के सदस्यों की

बैठक बक्शी का तालाब ब्लॉक (बीकेटी) के कठवारा पंचायत भवन में आयोजित हुई। इस मौके पर कठवारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डा. अवधेश ने कहा कि फाइलेरिया जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं। यह मच्छरजनित बीमारी है जो कि गंदे ठहरे पानी में मच्छरों के पनपने से होती है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। इस बीमारी में लिम्फ़ नोड प्रभावित होते हैं और एक बार जब यह रोग हो जाता है तो यह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है। दवा के सेवन से इस रोग को बढ़ने से रोका जा सकता है। यह बीमारी व्यक्ति को आजीवन विकलाँग बना देती है। फ़ाईलेरिया रोगियों के क्लस्टर फोरम के सदस्य इस बीमारी को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वह ग्राम या स्थानीय स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर फाइलेरिया रोग के जांच, उपचार, कारण और भ्रांतियों को दूर करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

इस मौके पर स्वयंसेवी संस्था पाथ के प्रतिनिधि डा. शोएब ने कहा कि फ़ाईलेरिया से बचाव के लिए सरकार द्वारा साल में एक बार सामूहिक दवा सेवन(एमडीए) अभियान चलाया जाता है। इसके तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर–घर जाकर लोगों को एल्बेंडाज़ोल और डाईइथाइलकार्बामजीन (डीईसी) की गोलियाँ खिलाते हैं। इन दवाओं का लगातार पाँच साल तक साल में एक बार सेवन करने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। दो साल से कम आयु के बच्चों, गर्भवती और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को इस दवा का सेवन नहीं करना होता है। इन दवाओं के सेवन का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। कुछ लोगों में दवा के सेवन के बाद चक्कर आना, जी मिचलाना जैसे दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं जिससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह अपने आप ठीक हो जाता है। इसका मतलब यह होता है कि उसके शरीर में फाइलेरिया के रोगियों की पहचान के लिए साल में एक बार नाइट ब्लड सर्वे किया जाता है। रात में लोगों के खून के नमूने की जांच कर संक्रमण की स्थिति का पता लगाया जाता है क्योंकि फाइलेरिया के जीवाणु, जिन्हें हम माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं वह रात में सक्रिय होते हैं। इसलिए फाइलेरिया के मरीजों को चिन्हित करने का काम रात में ही किया जाता है।

बैठक में समूह को विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से फाइलेरिया पर जागरूक किया गया। उन्हें व्यायाम का अभ्यास व सूजन वाली जगह की साफ़–सफाई कैसे रखनी है इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया।

इस मौके पर कठवारा के ग्राम प्रधान अशोक कुमार, पंचायत सहायक विनय कुमार , सीफार के प्रतिनिधि और क्लस्टर फोरम के 13 सदस्य उपस्थित रहे।

लखीमपुर खीरी कोतवाली निघासन, खीरी04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवध की आवाज ब्यूरो

लखीमपुर खीरी। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद स्तर पर चलाये जा रहे वारण्टी / वाछिंत / संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र0नि0 श्री चन्द्रभान यादव थाना निघासन के कुशल मार्गदर्शन में निघासन पुलिस बल

द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्त 1. कुवारे पुत्र दीपक निवासी बंगलहाकुटी थाना निघासन खीरी सम्बन्धित मु0सं0 3790–16 धारा 323,504 आईपीसी 2. सज्जिलके उर्फ सोनू पुत्र श्रीकेशन निवासी बंगलाकुटी थाना निघासन खीरी मु0सं0 3790–16 धारा 323,504 आईपीसी दिनांक 3.मझिलके पुत्र श्रीकेशन निवासी बंगलहाकुटी थाना निघासन खीरी सम्बन्धित मु0सं0 3790–16 धारा 323,504 आईपीसी 4. दिनेश पुत्र कामता प्रसाद निवासी सहतेपुरवा मजरा लुधौरी थाना निघासन खीरी इन वारण्टी अभियुक्तगण को इनके घर से गिरफ्तार किया गया है। नियमानुसार कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.उ0नि0 रामगौरव थाना निघासन 2.का0 सुभाष थाना निघासन

शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रम की समीक्षा बैठक सफ़लतापूर्वक संपन्न

अवध की आवाज ब्यूरो

अयोध्या। जिलाधिकारी नितीश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रम (37 प्रारूप) माह जनपद अक्टूबर 2022 की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डेन कार्ड बनाने के कार्य में और तेजी लाने तथा समस्त पात्र व्यक्तियों को शीघ्र से शीघ्र योजना से आच्छादित करने के निर्देश दिये तथा फसल बीमा योजना के तहत आच्छादित फसलों के नुकसान का नियमानुसार अनुमन्य लाभ किसानों को सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु उपनिदेशक कृषि को निर्देशित किया। इस अवसर पर 50 लाख से अधिक लागत की निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा में जिलाधिकारी ने समस्त अधूरे निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन 100 शैय्या चिकित्सालय कुमारगंज तथा 50 शैय्या चिकित्सालय देवगांव के अधूरे कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की तथा कार्यदायी संस्था पर कठोर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने नई सड़कों का निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। आईटीआई मिल्कीपुर से निर्माण कार्य की धीमी प्रगति तथा कार्य की गुणवत्ता सही नही बताये जाने पर सम्बंधित कार्यदायी संस्था के जे0ई0 व ए0ई0 का वेतन रोकने व स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन कार्यों के सम्बंधित जनपदीय विभागाध्यक्ष को अपने–अपने विभाग के कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने तथा कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर सम्बंधित कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी तय करने व कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, मुख्य विकास अधिकारी, एडीएम वित्त एवं राजस्व, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उपनिदेशक कृषि, बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।

एनटीपीसी सिंगरौली स्वच्छ भारत के प्रति प्रतिबद्ध

अवध की आवाज ब्यूरो

जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश। एनटीपीसी सिंगरौली शक्तिनगर द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार स्वच्छ भारत अभियान के तहत नैगम सामाजिक दायित्व के अंतर्गत शान्ति निकेतन जन सेवा समिति, वाराणसी के कलाकारों द्वारा परियोजना समीपवर्ती गाँवो के विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कुमार आदर्श, कार्यपालक (सीएसआर) एनटीपीसी सिंगरौली द्वारा बच्चों को स्वच्छता किट का वितरण भी किया गया एवं बच्चों को स्वच्छता के प्रति प्रोसाहित किया गया। उक्त कार्यक्रम का आयोजन प्राथमिक विद्यालय– शक्तिनगर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय शक्तिनगर, प्राथमिक विद्यालय– कोटा बाबू एवं कम्पोजीट विद्यालय–कोटा पुनर्वास, कम्पोजीट विद्यालय–तारापुर, प्राथमिक विद्यालय–परसवार राजा, कम्पोजीट विद्यालय– चिल्काडांड, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, लोझरा एवं परियोजना प्रभावित गाँवों के नुक्कड़ों

पर किया गया इस अवसर पर उक्त सभी विद्यालयों की प्रधानाध्यापिकायें, शिक्षकगण, अभिभावकगण, हीरालाल–ग्राम प्रधान चिल्काडांड, जन प्रतिनिधि सहित ग्रामीण एवं एनटीपीसी सिंगरौली की सीएसआर टीम के साथ, हरीश वर्मा, एसोसिएट कर्मचारी विकास केंद्र एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद रहें।

नियमित टीकाकरण को लेकर युनिसेफ द्वारा समुदायिक बैठक आयोजित

अवध की आवाज ब्यूरो

डुमरियागंज (सिद्धार्थ नगर)। यूनिसेफ के सहयोग से नियमित टीकाकरण से अधिक उदासीन परिवार एवं टीकाकरण से इनकार

करने वाले परिवारों को चिन्हित कर सामुदायिक बैठक कर टीकाकरण के प्रति लोगो को जागरूक किया जा रहा है।इसी क्रम में शुक्रवार को ग्राम परसा इमाद में पूर्व प्रधान माधुरी देवी के निवास पर यूनिसेफ बीएमसी शोएब अख्तर द्वारा बैठक का टीकाकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं महत्व को बताया गया। तथा 5 साल 7 बार टीका छूटे ना एक भी बार पर चर्चा किया गया। बैठक में शोएब अख्तर ने कहा कि नियमित टीकाकरण बहुत जरूरी है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्वास्थ विभाग द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस कार्य में प्रत्येक परिवार का सहयोग जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ परिवार टीकाकरण को लेकर असहज महसूस करते हैं और उदासीनता बरतते हुए टीकाकरण में भाग नहीं लेते हैं। ऐसे परिवारों को चिन्हित करते हुए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तिथि में टीकाकरण कैंप लगाया जाता है सभी लोग इसमें अवश्य भाग ले। बैठक में ए एन एम नीलम भारती एवं आशा उषा देवी, गुड़िया द्वारा उदासीन परिवार के बारे में चर्चा करते हुए उनकी भ्रांतियों को दूर किया गया। सी एच ओ मेराज आलम द्वारा सभी को बताया गया परसा इमाद ग्राम में हेल्थ वैलनेस सेंटर संचालित है। पर्याप्त मात्रा में दवाएं हैं तो जरूर सम्पर्क करें। सामुदायिक बैठक में मुख्य रूप से संगिनी अनीता पांडे, कौसर जहां, रीमा, पुष्पा लवली सीमा ,सुनीता ,रामफेर, विनोद कुमार ,हरिराम आदि मौजूद रहे।

कैंट बोर्ड में सफाई कर्मियों के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर पूर्व कैंट विधायक सोहिल अख्तर अंसारी ने मुख्य अधिशासी को सौंपा ज्ञापन

अवध की आवाज ब्यूरो

उन्नाव। कानपुर बातचीत के दौरान हमारे संवाददाता को बताया गरीब मजलूम सफाई कर्मी के साथ

ठेकेदार घोर अन्याय कर रहा है जिसका हम विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे रु663 पर आदमी को दिया जा रहा था महीने में 15000 कुछ रुपए होते हैं उसको ठेकेदार ने काटकर रु12000 कर रखा है जिसके कारण सफाई कर्मियों में आक्रोश है कैंट बोर्ड के अधिशासी अधिकारी ने आश्वासन देते हुए बोले रु663 पर सफाई कर्मियों को दिया जाएगा साथ ही जो सफाई कर्मी हटाए गए हैं उनको वापस लिया जाएगा।

प्रदेश के आयुर्वेदिक कॉलेजों में पीजी की 48 सीटों की मान्यता रद्द, तीन कॉलेजों में थीं 95 सीटें

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के तीनों सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेजों में स्नातकोत्तर (पीजी) की 95 में 48 सीटों की मान्यता रद्द कर दी गई है। इससे कई विभागों में अब स्नातकोत्तर की पढाई बंद हो गई है। मान्यता रद्द होने के पीछे संबंधित विभागों में संकाय सदस्यों की कमी होना बताया गया है। प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी और पीलीभीत के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में स्नातकोत्तर की सीटें हैं। इन सीटों पर दाखिले से पहले नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की टीम (एनसीआईएसएम) की टीम निरीक्षण कर व्यवस्था की जांच करती है। इसके बाद ही यहां पीजी कोर्स चलाने की मान्यता देती है। बताया जाता है कि पीजी की काउंसिलिंग से पहले टीम ने निरीक्षण किया तो तीनों कॉलेजों में संकाय सदस्यों की नहीं मिले। ऐसे में यहां के विभिन्न विभागों की पीजी की सीटें खत्म कर दी हैं। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज दूडियागंज लखनऊ में पीजी की 49 सीटें हैं। यहां की रचना शरीर, क्रिस्या शरीर विभाग की पांच–पांच और बाल रोग व कौमारभृत्य विभाग की छह– छह सीटों की मान्यता रद्द कर दी है। यहां कुल 22 सीटों की मान्यता रद्द की गई है। इसी तरह राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी की 39 सीटों में 19 सीटों की मान्यता खत्म की गई है। इसमें शल्य की सात, गायनी की सात और रोग निदान विभाग की पांच सीटें हैं। इसी तरह राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत की द्रव्य गुण की सभी सात सीटों की मान्यता रद्द कर दी गई है।

60 फीसदी से ज्यादा खाली है अध्यापकों के पद

राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों में 60 फीसदी से ज्यादा पद खाली हैं। करीब तीन सौ पद के लिए अधियाचन भेजा गया था, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं हो पाई है। इसी तरह जो पहले से कार्यरत हैं, उनकी प्रोन्नति का मामला भी अटका हुआ है। बताया जाता है कि वर्ष 2019 में विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की प्रक्रिस्या हुई थी, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया।

प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह

अवध की आवाज ब्यूरो

सीतापुर। लोक निर्माण खंड चार द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत फर्रकपुर पुल से धन्नांग होकर सीतापुर लखीमपुर मार्ग को जोड़ने वाली सड़क पर चल रहे निर्माण कार्य में की जा रही अनियमिताओं के संबंध में किसान मंच राष्ट्रीय सचिव/प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से जांच की मांग की है!प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए निश्चित मापदंडों की अनदेखी करते हुए किए जा रहे निर्माण कार्य पर आपत्ति करते हुए किसान नेता ने कहा यह कैसी विडम्बना है कि विकास के लिए निर्गत धनराशि की खुलेआम लूट चल रही है, और जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती!विगत चार वर्ष पहले इसी सड़क पर साढ़े तीन करोड़ से

अधिक के बजट से निर्माण किया गया था,जो दो वर्षों के अंदर गड्ढों में तब्दील हो जाने के बाद अभी कुछ दिनों पहले इसी सड़क के मरम्मत के नाम पर कागजी कार्य संपन्न हो चुका है!और अब प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत चल रहे निर्माण में भी जिम्मेदार अधिकारी कागजी कार्रवाई पूरी कर अपना उल्लू सीधा करने में व्यस्त हैं!जिला प्रशासन द्वारा इस प्रकरण की जांच कर हो रही लूट में शामिल जिम्मेदारों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी! अन्यथा की स्थिति में किसान मंच द्वारा चल रहे निर्माण के विरुद्ध आंदोलन किया जाएगा,जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

विश्व निमोनिया दिवस (12 नवंबर) पर विशेष

निमोनिया होने पर समय से इलाज़ है बेहद जरूरी

अवध की आवाज ब्यूरो

लखनऊ। हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को निमोनिया के प्रति जागरूकता पैदा करना है। वैसे तो

निमोनिया की बीमारी कभी भी हो सकती है पर आमतौर पर छोटे बच्चों को निमोनिया जल्दी हो जाता है। इस बीमारी में फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं और कफ, बुखार, सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानियां होने लगती है। ऐसे में समय पर इलाज़ होना बेहद जरूरी है वरना थोड़ी सी लापरवाही से भी गंभीर समस्या हो सकती है।

यदि हम पाँच साल तक की आयु के बच्चों में होने वाली मृत्यु की बात करे तो एक प्रमुख कारण निमोनिया है। यूनिसेफ़ के अनुसार इससे हर साल दुनिया में 7 लाख से अधिक की मृत्यु होती है। साल 2021 में देश में पाँच साल तक की आयु के 69 फीसद बच्चों को निमोनिया संबंधी सलाह और जांच स्वास्थ्य केंद्रों पर मिली। एसजीपीजीआई की वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डा.पियाली भट्टाचार्या बताती हैं कि इस बीमारी का पूरी तरह से उपचार संभव है और एंटीबायोटिक्स के द्वारा इसका प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है। निमोनिया में फेफड़ों का संक्रमण बैक्टीरिया, वायरस एवं फंगस के संक्रमण से होता है। जिससे कि दोनों फेफड़ों में सूजन आ जाती है या उसमें तरल पदार्थ भर जाता है। इसके लक्षण सर्दी जुकाम के लक्षण से बहुत अधिक मिलते हैं इसलिए जब भी ऐसा कुछ लगे तो पहले इसके लक्षणों की पहचान कर लें।

डा. पियाली का कहना है कि बच्चों में निमोनिया का मुख्य कारण कम वजन का होना, कुपोषण, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना, छह माह तक केवल स्तनपान न कराया जाना, घरेलू प्रदूषण , टीकाकरण न होना तथा जन्मजात विकृतियाँ जैसी हृदय संबंधी, अस्थमा, कटे होंठ एवं तालू होना है। पाँच साल तक की आयु के बच्चों में, 15 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु निमोनिया के कारण होती है।

डा. पियाली बताती हैं कि निमोनिया से बचाव के लिए न्यूमोकोकलकोन्जुगेट (पीसीवी) का टीका लगवाना चाहिए। यह बच्चे को डेढ़ माह, ढाई माह, साढ़े तीन माह और 15 माह में लगाए जाते हैं। इसके साथ ही समय से इन्फ्लुएंजा व खसरे का टीका लगवाना चाहिए। यह भी निमोनिया से बचाव करता है।

साथ ही घर व आस–पास सफाई, पीने का साफ पानी होना चाहिए, घर प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। इसके अलावा केवल स्तनपान समुचित पूरक आहार का सेवन, संतुलित और पौष्टिक आहार, विटामिन ए की दवा का सेवन कराना चाहिए। इससे निमोनिया सहित कई बीमारियों से बचाया जा सकता है।

सर्दी का मौसम आ गया है। ऐसे में बच्चों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। थोड़ी सी लापरवाही निमोनिया बीमारी को दस्तक दे सकती है।

बच्चों को ठंड से बचाएँ। बच्चे की सांस यदि तेज चले,कफ की आवाज आए तो निमोनिया हो सकता है। निमोनिया के अन्य लक्षणों में सामान्य से तेज़ सांस या सांस लेने में परेशानी, सांस लेते या खांसते समय छाती में दर्द, खांसी के साथ पीले, हरे या जंग के रंग का बलगम, बुखार, कंपकंपी या ठंड लगना, पसीना आना, होंठ या नाखून नीले होना, उल्टी होना, पेट या सीने के निचले हिस्से में दर्द होना, कंपकंपी, शरीर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द भी हैं।

आरक्षण के इंतजार में बढ़ी दिक्कतें : लखनऊ में पार्टी मुख्यालय से लेकर मंत्रालय तक के चक्कर लगा रहे दावेदार

लखनऊ। नगर निकाय चुनाव के आरक्षण के इंतजार में महापौर से लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदारों के साथ राजनीतिक दलों दिक्कतें बढ़ती जा रही है। आरक्षण निर्धारित होने से पहले ही सभी नगर निगमों में महापौर और प्रमुख नगर पालिका परिषदों में अध्यक्ष पद के दावेदारों की लंबी सूची बन गई है। इससे एक ओर जहां दावेदारों के बीच राजनीतिक खींचतान बढ़ रही है। वहीं आरक्षण निर्धारण और अधिकृत प्रत्याशी घोषित होने के बाद राजनीतिक दलों के सामने असंतोष को थामने की बड़ी चुनौती होगी।

प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा भाजपा सरकार बनने के बाद निकाय चुनाव को लेकर दावेदारों ने करीब छह महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। खासतौर पर विधायक का टिकट मिलने से वंचित रहे नेता नगर निगम में महापौर और नगर पालिका परिषदों में अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर उसी वर्ग के प्रत्याशी उतारे जाने हैं। लिहाजा टिकट की दावेदारी को लेकर सबसे ज्यादा संघर्ष सामान्य वर्ग की सीटों के लिए है। पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को साधे रखने के लिए भाजपा सहित सभी राजनीतिक दल सामान्य की सीट पर भी पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाएंगे। ऐसे में सामान्य वर्ग के दावेदारों की दिक्कतें भी बढ़ी हुई है।

पार्टी मुख्यालय से मंत्रालय तक चक्कर लगा रहे दावेदार

नगर निगम के वर्तमान महापौर और नगर पालिका परिषद के मौजूदा अध्यक्षों के साथ आगामी चुनाव में इन पदों पर टिकट के दावेदार आरक्षण के लिए पार्टी मुख्यालय से लेकर नगर विकास मंत्रालय तक चक्कर लगा रहे है। दावेदार पार्टी में चुनाव प्रबंधन से जुड़े पदाधिकारियों को अपने अपने हिसाब से आरक्षण निर्धारण को लेकर संतुष्ट करने में जुटे हैं। वहीं मंत्रालय से भी संभावित आरक्षण के लिए पूछताछ कर रहे हैं।

दिग्गजों के अरमानों पर फिर जाएगा पानी

प्रदेश सरकार के मंत्रियों, पार्टी के सांसद और विधायकों के रिश्तेदारों के साथ पूर्व विधायक भी नगर निगम में महापौर और नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे है। 2011 की जनगणना और चक्रानुम के हिसाब से सभी दिग्गज दावेदार अपनी–अपनी सीट को खुद के हिसाब से आरक्षित होना तय मान रहे है। जानकारों का मानना है कि निकाय चुनाव के लिए आरक्षण निर्धारित होने के बाद कई दिग्गजों के अरमानों पर पानी फिर जाएगा। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि मंत्रियों, विधायकों और सांसदों ने आरक्षण अनुकूल नहीं होने पर अपने करीबी दूसरी जाति के उम्मीदवार भी तैयार कर रखे हैं।

सपा और बसपा का विकल्प चुन सकते हैं दावेदार

पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के सामने चुनाव में जीत के साथ असंतोष रोकने की भी बड़ी चुनौती है। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष का टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदार सपा और बसपा से टिकट लेने का विकल्प चुन सकते हैं। निकाय चुनाव बेहद स्थानीय होने के कारण दावेदारों की बगावत और उनके समर्थक कार्यकर्ताओं की नाराजगी का असर चुनाव पर पड़ेगा।

ट्रक चालक की लापरवाही से शिक्षिका की दर्दनाक मौत

अवध की आवाज ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या अकबरपुर आजमगढ़ राज्यमार्ग पर भयंकर दुर्घटना में शिक्षिका की मौत हो गई है,घटना आज सुबह लगभग 8रू40 की बताई जा रही है जिसके अनुसार पूरा बाजार के पूर्व आजमगढ़ की तरफ बच्चूलाल इंटर कालेज के थोड़ा आगे भारत पेट्रोलपंप के पास निर्माणाधीन पुलिया के ऊपर स्कूटी से जा रही शिक्षिका की एक ट्रक चालक की लापरवाही से दुर्घटना हो गई जिसमे मौके पर ही शिक्षिका की मौत हो गई।सूत्रों के अनुसार शिक्षिका मोजनपुर टांडा जिला अंबेडकरनगर की रहने वाली थी जो फैजाबाद के देवकाली के पास रहती थी और विकासखंड मया के दामोदरपुर प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति थी।शिक्षिका फैजाबाद से प्रतिदिन विद्यालय अपनी स्कूटी से आती जाती थी जिसके स्कूटी का नंबर UP42 AW 5869 हैं। घटना की सूचना पर तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और लाश को निकलवा कर कानूनी कार्यवाही पूरी कर रही है।

अपहरण कर किशोरी से पांच दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म, बिहार ले जाकर युवकों ने की वारदात

कुशीनगर। कुशीनगर जिले के बरवापट्टी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी का अपहरण कर पांच दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि दो युवक किशोरी का अपहरण कर उसे बिहार ले गए। हालत बिगड़ने पर पिता के पास छोड़कर आरोपी फरार हो गए। किशोरी का उपचार कराने के बाद पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। एसओ का कहना है कि तीन लोगों के खिलाफ तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार बरवाट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी के पिता ने पुलिस को तहरीर दी है। पिता ने पुलिस को बताया है कि दो नवंबर की रात उनकी नाबालिग बेटी घर से थोड़ी दूरी पर नित्यक्रिया के लिए गई थी। तभी बाइक सवार दो युवकों ने उसके मुंह और आंख में कपड़ा बांधकर अपहरण कर लिया। उसे धमकाकर किसी अज्ञात जगह पर ले गए। फिर वहां से उसे बिहार के रंगललही गांव के पास एक घर में ले जाकर बंधक बना लिया। किशोरी को कमरे में बंद करके दोनों युवकों ने उसके साथ पांच दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया। सात नवंबर की दोपहर किशोरी की हालत बिगड़ने पर दोनों ने युवकों ने पिता को फोन करके बुलाया। रात में नौ बजे बेटी की तलाश करते हुए पिता जब रंगललही गांव में पहुंचे। दोनों आरोपी किशोरी को उनके पास छोड़कर भाग गए। बेटी की हालत देखकर घबराए पिता ने उसका उपचार कराया। इसके बाद घर लौटकर घटना की सूचना पुलिस को दी। किशोरी के पिता का आरोप है कि अपहरण के आरोपी दोनों युवक उनके बगलगीर महिला के रिश्तेदार हैं। महिला की मदद से ही दोनों युवकों ने किशोरी का अपहरण करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस संबंध में एसओ जितेंद्र कुमार टंडन ने बताया कि घटना की तहरीर मिली है। इस मामले की छानबीन की जा रही है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रपिता स्मारक इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने लिया आजीवन नशामुक्त रहने का संकल्प

अवध की आवाज ब्यूरो

लखनऊ। केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर के नेतृत्व में नशामुक्त समाज आंदोलन–अभियान कौशल का पूरे देश में वृहद स्तर पर संचालित हो रहा है। इसी कड़ी में नगर पंचायत इटौंजा के राष्ट्रपिता स्मारक इंटर कॉलेज में संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस कॉलेज के करीब दो हजर छात्र–छात्राओं एवं शिक्षकों को जीवन पर्यंत नशामुक्त रहने का संकल्प लिया। जिला प्रभारी अनिल कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में बीकेटी ब्लॉक प्रभारी नागेन्द्र बहादुर सिंह चौहान व अभियान सहयोगी अभिषेक अवस्थी नशामुक्ति का अमृत कलश लेकर बख्शी का तालाब के गांव–गली में घूम रहे हैं। वह क्षेत्र के छात्र–छात्राओं, शिक्षक–शिक्षिकाओं व अभिभावकों को नशे के प्रति जागरूक कर रहे हैं। सभी को आजीवन नशामुक्त रहने का संकल्प करवाते हैं। छात्र–छात्राओं व शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के नशों से होने वाली व्यापक जनहानि, धनहानि और मानहानि के बारे में विस्तृत ढंग से बताया। कॉलेज के सभी छात्र–छात्राओं ने अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का नशा न करने का वचन दिया। सबने वादा किया कि वे अपनी दोस्ती, अपने विद्यालय और अपने परिवार को सदैव नशामुक्त रखेंगे। साथ ही, वे भारत को नशामुक्त बनाने में अपना योगदान देंगे। इस कार्यक्रम में आंदोलन के जिला प्रभारी श्री अग्रवाल की तरफ से कार्यवाहक प्रधानाचार्य मिथिलेश कुमार पाण्डेय व सबसे सीनियर शिक्षक दिनेश कुमार वर्मा को सम्मानित किया गया। इस संकल्प सभा का आयोजन बीकेटी इंटर कॉलेज के छात्र प्रभात यादव ने किया था।

'नीमट्री हेल्थकेयर टियर 2-3 शहरों में बेहतरीन इलाज की पेशकश करेगा'

अवध की आवाज ब्यूरो

लखनऊ। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रसिद्ध नाम, नीमट्री हेल्थकेयर ने देश के टियर 2/3 शहरों में सर्वश्रेष्ठ आर्थोपेडिक उपचार प्रदान करने के लिए अपनी अनूठी पहल शुरू की है। इसके तहत वर्तमान में दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों के चुनिंदा शहरों में सबसे अच्छा इलाज उपलब्ध है। उसी पर बात करते हुए, इस हेल्थकेयर स्टार्ट–अप के सीईओ श्री अजय जग्गा ने कहा कि हमारा मिशन देश भर में सस्ती दरों (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त उपचार सहित) पर गुणवत्तापूर्ण आर्थोपेडिक उपचार प्रदान करना है। हमारे विजन के अनुरूप– 2025 तक नेशनवाइड प्रजेंस के साथ परामर्श और सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए सबसे भरोसेमंद जोड़ खुशियों का ऑर्थो ब्रांड बनने के लिए, हम तेजी से पूरे उत्तरी राज्यों में काम करेंगे। नीमट्री हेल्थकेयर के निदेशक डॉ. पंकज बजाज (जो खुद एक प्रसिद्ध हड्डी रोग सर्जन हैं) ने कहा, "हम सभी रोगियों को ऑर्थो–केयर की जरूरत के लिए वन–स्टॉप समाधान प्रदान करते हैं। फ्रैक्चर से लेकर ट्रॉमा तक, स्पोर्ट्स इंजरी से लेकर स्पाइन सर्जरी आदि तक जॉइंट रिप्लेसमेंट तक। हमारी टीम मरीजों की सुविधा के अनुसार अस्पतालों में या घर पर सर्जरी के बाद की देखभाल, होम केयर और फिजियोथेरेपी सत्र में प्रवेश से पहले डिजिटल रूप से अच्छी तरह से सुसज्जित है। डॉ. बजाज ने आगे कहा, एनसीआर और अन्य राज्यों में एसेट–लाइट मॉडल पर अस्पतालों के ऑर्थो विभागों का अधिग्रहण, ट्रॉमा और अन्य आपातकालीन जरूरतों के लिए हमारे पूर्णकालिक ऑर्थो सर्जन और सहायक कर्मचारियों को रखना, बड़े शहरों के वरिष्ठ सर्जनों को अनुसूचित आपातकालीन प्रदर्शन के लिए जुटाना है। सर्जरी – हमें अद्वितीय और दूसरों से अलग बनाती है। वास्तव में कोई अन्य कंपनी ऐसी गतिविधियां नहीं कर रही है। इस ऑर्थो स्टार्ट–अप ने 100 वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञों के साथ करार करने का दावा किया है, 40,000 रोगियों के जीवन को छुआ है, 35 संबद्ध अस्पतालों में 4,000 सर्जिकल प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया है, जिसमें टियर 2/3 शहरों पर प्रमुख ध्यान दिया गया है।

लिंकन फार्मास्युटिकल्स का शुद्धलाभ 57.85 प्रतिशत बढ़कर 23.74 करोड़ रूपये हुआ

लखनऊ। भारत की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनियों में से एक लिंकन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने बीते 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में 57.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। कम्पनी ने वित्तीय परिणामों की जानकारी देते हुये बताया कि वित्त वर्ष 2023 के पहली तिमाही में रु. 15.04 करोड़ के शुद्ध लाभ के मुकाबले 23.74 करोड़ रूपये है, जो 57.85 प्रतिशत की वृद्धि है। सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए संचालन से कुल आय रु. 146.30 करोड़ दर्ज की गई, जो कि वित्त वर्ष 2023 के पहली तिमाही की 130.00 करोड़ रूपये के संचालन से कुल आय की तुलना में 12.54 प्रतिशत अधिक है। सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए एबिटा रु. 34.59 करोड़ दर्ज की गई जबकि वित्त वर्ष 2023 के पहली तिमाही में 23.41 करोड़ रूपये की तुलना में 47.76 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई गई। वित्त वर्ष 2023 के दूसरी तिमाही के लिए प्रति शेयर आय (इपीएस) रु. 11.84 प्रति शेयर पर रिपोर्ट किया गया था जबकि वित्त वर्ष 2023 के पहली तिमाही में रु. 7.49 की तुलना में 58.08 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई गई थी। शेयरधारकों ने 30 सितंबर, 2022 को आयोजित 28वीं एजीएम में वित्तीय वर्ष 21–22 के लिए प्रति शेयर रु. 1.50 रूपये के लाभांश को मंजूरी दी। वर्ष के दौरान कंपनी को सेफलोस्पोरिन संयंत्र में टैबलेट कैप्सूल, ड्राई–पाउडर सस्पेंशन उत्पादों के लिए डब्ल्यूएचओ–जीएमपी से मंजूरी मिली। इस संयंत्र से उत्पादन इस साल पिछली तिमाही से होने की उम्मीद है। लिंकन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के प्रबंधा निदेशक महेंद्र पटेल ने परिणामों और प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा कंपनी ने तिमाही के दौरान एक मजबूत परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन दिया है और भविष्य में हमारे विकास संख्या में सुधार करने के लिए आश्वस्त है। हाल ही में कंपनी को ऑस्ट्रेलिया के मेडिसिन्स एंड मेडिकल डिवाइसेज रेगुलेटर– थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपनी खात्रज फैसिलिटी के लिए अप्रूवल मिला है। टीजीए और ईयू जीएमपी अनुमोदन निर्यात बाजार में कंपनी की उपस्थिति को और मजबूत करेंगे। रणनीतिक विकास पहल, उत्पाद और भौगोलिक विस्तार, परिचालन दक्षता निकट से मध्यम अवधि में सभी हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करने की संभावना है।

सैमको म्यूचुअल फंड ने पेश किया विशिष्ट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड जो मुख्य रूप से मिड एवं स्मश्वल कैप कंपनियों में करेगा निवेश

एनएफओ 15 नवंबर 2022 को खुलेगा और 16 दिसंबर को बंद होगा

लखनऊ। सैमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड कुशल मिड–कैप और स्मॉल–कैप बिजनेस का एक पोर्टफोलिया होगा. इस ईएलएसएस में अनिवार्य तौर पर तीन साल का लॉक–इन पीरियड होगा जो धन सृजन का एक शानदार माध्यम साबित हो सकता है। निवेशकों को मजबूत बुनियाद और भविष्य में धन सृजन की अत्यधिक संभावनाओं वाले बिजनेसेज में निवेश करने में मदद करने को लेकर सैमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है। यह टेक्नोलॉजी पर आधारित एक प्रोपरायटरी रणनीति है जिसके जरिए निवेश करने योग्य उच्च गुणवत्ता वाले अच्छे शेयरों को चुना जाता है. फंड मैनेजमेंट टीम ऐसी निवेश योग्य कंपनियों का विश्लेषण करती है और पूंजी के आधार पर उच्च समायोजित रिटर्न देने में सक्षम ग्रोथ–ओरिएंटेड (वृद्धि उन्मुखी) बिजनेसेज का एक पोर्टफोलियो तैयार करती है। तीन साल के औसत रोलिंग रिटर्न के आधार पर ये बात सामने आती है कि निफ्टी मिडस्मॉलकैप 400 इंडेक्स ने एक अप्रैल, 2005 के बाद से निफ्टी500 इंडेक्स की तुलना में आठ फीसदी ज्यादा रिटर्न दिया है (डिस्क्लेमरः अतीत का प्रदर्शन भविष्य में बरकरार रह भी सकता है और नहीं भी. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि ये रिटर्न एक इंडेक्स का है ना कि किसी खास स्कीम का). मिड–कैप और स्मॉल–कैप बिजनेसेज की एक साल की होल्डिंग की तुलना में तीन साल की होल्डिंग से बाजार के उतार–चढ़ाव का असर काफी कम रह जाता है। ऐसे में कोई भी निवेशक कम–से–कम तीन साल तक होल्डिंग के साथ ऐसे फंड्स से उच्च जोखिम–समायोजित रिटर्न हासिल कर सकता है जिसका एक्सपोजर मिड–कैप एवं स्मॉल–कैप बिजनेसेज में होता है। इंडस्ट्री में एक मिथक है कि आम तौर पर मिड–कैप्स और स्मॉल–कैप्स उनके आकार की वजह से खराब क्वालिटी के बिजनेस होते हैं. दूसरी ओर असलियत में कुछ बिजनेसेज आकार में छोटा होने के बावजूद अपनी श्रेणी में शीर्ष पर होते हैं जिनकी आमदनी से जुड़ा ग्रोथ ठोस होता है. सही कंपनी में निवेश करने के लिए बिजनेस की विशेषताओं को समझना आवश्यक होता है जो ऐसी कंपनियों को आने वाले समय में बड़ी कंपनी बनाती हैं क्योंकि एक मिड–कैप स्टॉक अपने लाइफटाइम में दो तरह के नतीजे दे सकता है– एक मिड–कैप स्टॉक बाद में एक स्मॉल–कैप स्टॉक यानी आपकी गाढ़ी कमाई को बर्बाद करने वाला साबित हो सकता है. दूसरी ओर, कोई मिड–कैप स्टॉक भविष्य में धन का सृजन करने वाला लार्ज–कैप स्टॉक भी बन सकता है। भारत में अधिकतर ईएलएसएस फंडस का एक्सपोजर लार्ज–कैप स्टॉक में होता है और उनकी शीर्ष होल्डिंग्स में कमोबेश एक ही तरह के कुछ स्टॉक होते हैं। इस वजह से किसी भी निवेशक के लिए इस तरह के अलग–अलग फंड्स में अंतर कर पाना काफी मुश्किल भरा होता है। वहीं, सैमको टैक्स सेवर फंड एक अलग तरह का फंड है क्योंकि यह मुख्य रूप से ऐसे मिड–कैप और स्मॉल–कैप हाई ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश करता है जिनमें भविष्य में काफी बेहतर प्रदर्शन करने की संभावनाएं मौजूद होती हैं और साथ–ही–साथ तीन साल के अनिवार्य लॉक–इन पीरियड से काफी अधिक उतार–चढ़ाव को कम करने में मदद मिलती है। सैमको म्यूचुअल फंड अपनी वेबसाइट पर ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के एक्टिव शेयर को हर दिन सार्वजनिक करेगा। पारस मटालिया, हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च, सैमको म्यूचुअल फंड ने कहा। "आप आज जिन लार्ज–कैप स्टॉक्स में निवेश करते हैं, वे अतीत में कभी मिड–कैप स्टॉक्स थे और मिड–कैप से लार्ज–कैप बनने की इस प्रक्रिया में निवेशकों ने काफी अधिक पैसे कमाए हैं. सैमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के साथ हम निवेशकों को सेक्शन 80C के तहत लाभ प्राप्त करने और कम–से–कम तीन साल तक कुशलतापूर्वक तरीके से वृद्धि हासिल करने वाले मिड कैप और स्मॉल–कैप बिजनेस बनने का एक्सपोजर प्रदान करते हैं. इसके पीछे का आइडिया निवेशकों को बढ़िया सेक्टरर्स की मिड और स्मॉल–कैप कंपनियों में निवेश के जरिए भारत की विकास यात्रा का भागीदार बनाने का है. इसकी वजह ये है कि ये बिजनेसेज भविष्य में देश की प्रगति के वाहक सिद्ध हो सकते हैं और वे काफी अधिक ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। पारस ने साथ ही कहा, "ऐतिहासिक तौर पर निफ्टी मिडस्मॉलकैप 400 टीआरआई ने तीन साल के एवरेज रोलिंग रिटर्न बेसिस पर निफ्टी 500 टीआरई की तुलना में आठ फीसदी ज्यादा रिटर्न दिया. तीन साल के लॉक–इन फीचर के साथ मिडकैप एवं स्मॉलकैप कंपनियों के पोर्टफोलियो से बहुत अधिक जोखिम समायोजित रिटर्न हासिल हो सकता है। ऋषि धवन, रीजनल हेड (नॉर्थ), सैमको ग्रुप कहा, "सैमको म्यूचुअल फंड खुदरा निवेशकों को सशक्त बनाना चाहता है और ऐसे समाधान पेश करना चाहता है जो उन्हें निवेश की यात्रा के दौरान स्मार्ट फैसले लेने में मदद करे. सक्रिय नवोन्मेषी उत्पाद क्यूरेट करने के सैमको के डीएनए के अनुरूप ईएलएसएस फंड मुख्य रूप से बहुत अधिक संभावनाओं वाले मिड एवं स्मॉलकैप कंपनियों में निवेश करेगा। डिस्क्लेमरः म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।डिस्क्लेमरः अतीत का प्रदर्शन भविष्य में बरकरार नहीं भी रह सकता है।

स्कोडा ऑटो इंडिया एक ग्रोथ हब के रूप में भारत के साथ नई बुलंदियों तक पहुंचा

लखनऊ। स्कोडा ऑटो इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ 2022 की पिछली तिमाही में बेहतरीन प्रदर्शन का जश्न मनाया। पीक–टु–पीक अभियान में जहां कंपनी की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया, वहीं इसके भारत निर्मित प्रॉडक्ट्स को देहरादून में हिमालय की खूबसूरत वादियों में हुये सम्मेलन में विशाल जनसमूह के सामने प्रदर्शित किया गया। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत और दुनिया भर के ऑटोमोटिव एक्सपर्ट शामिल हैं। स्कोडा ऑटो इंडिया ने कुशाक के लिए हाल ही में किए गए जीएनसीएपी क्रैश टेस्ट में फुल 5 स्टार क्रैश सेफ्टी रेटिंग हासिल करने का जश्न भी मनाया। स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रैंड डायरेक्टर पेट्र सॉल्क ने कहा आमतौर पर हम इस तरह के सम्मेलन का आयोजन अपने म्लाडा बोलेस्लाव हेडक्वॉर्टर में करते हैं और वहां अपने प्रॉडक्ट्स का प्रदर्शन करते हैं। इस बार मुझे पूरी दुनिया के ऑटो सेक्टर के दिग्गजों और प्रतिनिधियों के सामने भारत में विकसित और निर्मित प्रॉडक्ट्स का प्रदर्शन करते हुए भारत आने के लिए निमंत्रण देते हुए बहुत खुशी हुई और गर्व महसूस हुआ। इन मेड इन इंडिया प्रॉडक्ट्स ने पूरी दुनिया के सामने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है। यह स्कोडा ऑटो इंडिया में हम सबके लिए कुछ अविश्वसनीय दिनों में से एक थे, जिसमें हमने भारत और दुनिया भर के विशेषज्ञों से विचार–विमर्श किया। हिमालय की खूबसूरत वादियों में हमारे इंडिया 2.0 के हीरोज आत्मविश्वास, ऊर्जा और उत्साह से लबरेज रहे। 2022 हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्षों में एक रहा है। इस साल हमें जिस तरह का रेस्पॉन्स मिला, उसे देखकर हमें पूरा विश्वास है कि हम 2023 और उसके बाद भी इस गति को बनाए रखेंगे। इस सम्मेलन में भारत, जर्मनी, स्लोवाकिया, आयरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक के ऑटो क्षेत्र के दिग्गजों और उत्साही प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। स्कोडा ऑटो इंडिया ने कुशाक के एनिवर्सरी एडिशन की पेशकश की भी घोषणा की। मॉडल ईयर 2023 में कुशाक और स्लाविया, दोनों कारों के फीचर्स अपडेट किए जाएंगे। अभी साल 2022 को अलविदा कहने में हालांकि एक महीने से ज्यादा का समय शेष है, स्कोअडा ऑटो इंडिया ने जनवरी से अक्टूबर तक 44,500 कारों की बिक्री के साथ भारत में बिक्री के लिहाज से 2022 को सबसे बड़े साल के रूप में दर्ज किया। इसी अवधि में कंपनी की कारों की कई महीनों, तिमाही और पहली छमाही में रेकॉर्डतोड़ बिक्री हुई। इससे इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट, मेड–इन इंडिया, मेड–फॉर–इंडिया एमक्यूबी–ए0–आईएन प्लेटफॉर्म की सफलता का प्रदर्शन किया गया। जुलाई 2021 में लॉन्च की गई कुशाक एसयूवी और मार्च 2022 में लॉन्च की गई स्लाविया सेडान इसी प्लेटफॉर्म पर निर्मित है। इस वाहन के आने से भारतीय बाजार में कंपनी के विकास ने रफ्तार पकड़ी है और दर्जे में बढ़ोतरी हुई है। अब जर्मनी और चेक रिपब्लिक के बाद भारत दुनिया भर में स्कोडा ऑटो का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। यूरोप के बाहर भारत स्कोडा इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है। पिछले साल कुशाक में कार में बैठने वाले बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा के लिहाज से 5–स्टार रेटिंग अर्जित की। इस डबल स्कोर को हासिल करने के लिए यह भारत में बनी एकमात्र कार है।

कुशाक भारत में बनी पहली कार है, जिसका नए और सख्त जीएनसीएपी प्रोटोकॉल के तहत परीक्षण किया गया है। जीएनसीएपी की रेटिंग एमक्यूबी–ए0–आईएन प्लेटफॉर्म की प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता को उभारती है। इससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता न करने की स्कोडा ऑटो इंडिया की रणनीति भी उभरकर सामने आती है। स्लाविया और कुशाक ऐक्टिव एवं पैसिव सेफ्टीक फीचर्स से लैस है। इनमें व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति के लिए हेडरेस्ट के साथ थ्री–पॉइंट सीट बेल्ट शामिल है। इसमें छह एयरबैग्स के साथ रोलओवर प्रोटेक्शन, बच्चों की सुरक्षा के लिए आइसोफिक्स की सुविधा, हिल होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एबीएस के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक सिस्टम, मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक–ब्रेक–फोर्स का डिस्ट्रिब्यूशन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग और कैमरा के साथ रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे कई फीचर्स शामिल है।

स्कॉलरशिप के लिए 15 व 30 तक होगा आवेदन,

दिव्यांग छात्र छात्राएं कर सकते हैं आवेदन, प्रारंभिक से उच्च शिक्षा तक मिलेगी सहायता

अलीगढ़। विभिन्न संस्थानों से पढ़ाई करने वाले दिव्यांग छात्र–छात्राओं को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए सरकार की ओर से स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्कॉलरशिप का लाभ पाने के छात्र–छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसके बाद पात्रों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के तहत प्री–मैट्रिक (कक्षा 1 से 10वीं तक) के विद्यार्थियों को 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं पोस्ट मैट्रिक (10वीं के बाद की कक्षा में पढ़ने वाले) और टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थी 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण पारिशा मिश्रा ने जिले के सभी दिव्यांग विद्यार्थियों को जागरुक किया जा रहा है कि वह अपनी पात्रता के अनुसार जरूर आवेदन करें। कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षा तक के विद्यार्थियों को योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। सहायता राशि पात्र विद्यार्थियों के खातों में सीधे भेजी जाएगी।

इसके लिए प्री–मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास दिव्यांग छात्र–छात्राओ से शैक्षिणिक सत्र 2022–23 के लिए छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्हें www.scholarships.gov.in पर आवेदन करना होगा। इसके अलावा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबसाइट कपेंbilityaffairs.gov.in पर भी आवेदन कर सकते हैं। उप निदेशक ने बताया कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड और संस्थान से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें रेगुलर विद्यार्थी होना जरूरी है। प्री–मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियो के अविभावकों की अधिकतम आय 2.50 लाख और टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिए आय अधिकतम 6 लाख होनी चाहिए। योजना का लाभ पाने के लिए दिव्यांग विद्यार्थी का 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग होना आवश्यक है। इसके लिए उन्हें स्वास्थ्य विभाग के प्रमाणपत्र को साथ में संलग्न करना होगा। एक माता–पिता की अधिकतम दो दिव्यांग संतानें ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं। ऐसे विद्यार्थी जो किसी अन्य योजना के तहत स्कॉलरशिप या स्टाईपेड ले रहे हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पात्र युवा योजना की विस्तृत जानकारी www.scholarships.gov.in से हासिल कर सकते हैं।

जिले में डेंगू के 13 नए मरीज मिले,शहर में अब तक 284 मिल चुके हैं संक्रमित, 48 मामले अब भी हैं एक्टिव

अलीगढ़। अलीगढ़ में डेंगू का कहर लगातार जारी है और गुरुवार को भी 13 नए मरीज मिले हैं। जिसके बाद जिले में अब तक संक्रमित होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 284 हो चुकी है। जिले में एक साथ इतने मरीजों के पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य महकमें में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार रात डेंगू की रिपोर्ट जारी की। जिसमें शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक के लोग डेंगू की चपेट में पाए गए। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने तत्काल मरीजों के इलाज के लिए काम शुरू किया, वहीं गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिले में अब तक कुल 284 लोग डेंगू संक्रमित हो चुके हैं। जिसमें ज्यादातर स्वस्थ्य होकर अपने घर जा चुके हैं। लेकिन इसमें 48 मामले अब भी एक्टिव हैं और इनका इलाज जारी है। वहीं गुरुवार को पॉजिटिव आने वालों में जिनकी स्थिति गंभीर थी, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सामान्य मरीजों को दवाइयां दी गई हैं और उनकी मॉनीटरिंग की जा रही है। डेंगू पॉजिटिव आने वालो में 19 वर्षीय युवक एएमयू छात्र, 17 वर्षीय युवती बेगमबाग, 22 वर्षीय युवक लोधा, 33 वर्षीय महिला अतरौली, 45 वर्षीय व्यक्ति बृज धाम कालोनी, 19 युवती रामघाट रोड, 20 वर्षीय युवती माता वाली गली, 30 वर्षीय महिला ऊपरकोट, 50 वर्षीय महिला नौरंगाबाद, 32 महिला मोहननगर, 18 वर्षीय युवती नौरंगाबाद, 30 वर्षीय व्यक्ति राम नगर और 8 वर्षीय बालिका रघुवीर पूरी से संक्रमित पाई गई है। सीएमओ डॉ नीरज त्यागी ने बताया कि जिले में डेंगू के मरीज लगातार मिल रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आमजनों को भी जागरुक होने की जरूरत है। घर के आसपास कहीं पर भी पानी को इकट्ठा ना होने दें। क्योंकि इसी में मच्छर पनपते हैं। उन्होंने बताया कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है। इसलिए नियमित रूप से कूलर और पानी की टंकी की सफाई करें। नाली और नाले के आसपास मिट्ट्टी का तेल या काला तेल डाल दें। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार इलाकों में फॉगिंग कर रहा है और लोगों को भी जागरुक किया जा रहा है।

करंट से झुलसे लाइमैन का कटा पैर

अलीगढ़। डिवीजन थर्ड में बीते दिनों शारदा कॉम्प्लेक्स बिजली घर में लाइन सही करते समय झुलसे लाइनमैन का ऑपरेशन के दौरान पैर काटा गया है। घटना के बाद लाइनमैन का दिल्ली के सफदरंगज अस्पताल में इलाज चल रहा था और उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आने के कारण लाइनमैन बुरी तरह से झुलस गया था। गुरुवार को डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए ऑपरेशन किया, जिसमें उसका दाहिना पैर काटना पड़ा है। अभी भी लाइनमैन की हालत गंभीर है और उसे आईसीयू में ही रखा गया है। अलीगढ़ के भांकरी निवासी 30 वर्षीय गुलाम नबी विद्युत वितरण खंड तृतीय के शारदा काम्पलेक्स बिजली घर पर तैनात था। वह 2 नवंबर को 11 केवी लाइन पर कार्य करने पहुंचा था। जेई सुशील कुमार की मौजूदगी में लाइनमैन ने फोन पर शटडाउन मांगा। मगर एसएसओ ने दूसरे फीडर का शटडाउन दे दिया। जैसे ही लाइनमैन 11 हजार की लाइन पर काम करने पहुंचा तो उसे जोरदार करंट लगा और उसका पूरा शरीर झुलस गया। आनन–फानन में उसे निजी फिर मेडिकल कालेज ले जाया गया था। मगर हालत गंभीर पर उसी रात उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। संविदा कर्मचरी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह ने बताया कि कर्मचारी के पैर के साथ किडनी में भी समस्या आई है। इस कारण उसकी हालत नाजुक बनी है। उन्होंने बताया कि एसएसओ की गलती से यह हादसा हुआ है। इससे पहले भी 15 फरवरी को क्वार्सी क्षेत्र में हादसा हुआ था। वहीं एक्सईएन अमित कुमार ने बताया कि संविदा कर्मचारी का एक पैर कट गया है। मामले की जांच की जा रही है। विभाग की ओर से कर्मचारी की पूरी मदद की जा रही है। मुआवजा आदि के लिए जो भी प्रावधान है, उसे प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है, जिससे कर्मचारी की आर्थिक मदद हो सके।

एएमयू दंत चिकित्सकों ने इंडियन बोर्ड ऑफ फोरेंसिक ओडोनोटोलॉजी फैलोशिप कार्यक्रम पूरा किया

अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के डॉ जेड ए डेंटल कॉलेज के ओरल पैथोलॉजी एवं ओरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉ जूही गुप्ता और डॉ शहला खान ने भारतीय फोरेंसिक ओडोनोटोलॉजी बोर्ड के फैलोशिप कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, नई दिल्ली में एक वर्षीय पाठ्यक्रम के दौरान एक सप्ताह पर आधारित उनके व्यावहारिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दोनों चिकित्सकों को इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर महेश वर्मा और इंडियन एकाडमी ऑफ फारेंसिक मडीसिन के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश के वर्मा ने डज्ञ. जूही गुप्ता और डा. शहला खन को फैलोशिप सर्टीफिकेट प्रदान किया।

अवध की आवाज हिन्दी दैनिक, प्रकाशक ,मुद्रक व स्वामी,अनिल कुमार सिंह द्वारा स्काई लाइन प्रिन्टर्स,119/23 खन्दारी लेन, लालबाग, लखनऊ उ0प्र0 से मुद्रित तथा डी–97/3 व 7,सेक्टर–7, इन्दिरा नगर,लखनऊ,उ0प्र0 से प्रकाशित। सम्पादक अनिल कुमार सिंह फोन : 0522–4340954 मो0–7905407289, Email: avadhkiaawaz@gmail.com
R.N.I.- UPHIN/2012/45127
नोट : समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादोंका न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।